मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 28 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 9 – 15 जुलाई 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन: एक अन्य जुमला.....3

इतिहास मिटाने के लिए नहीं, याद रखने के लिए है.....5

प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी उज्ज्वला योजना की हकीकत.....9

आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी मात दो

लोकतंत्र, संविधान और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करो

किरणेश कुमार

पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक 24 जून 2023 को जनशक्ति भवन में मिथिलेश कुमार झा की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के महासचिव डी राजा ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र नाथ ओझा ने मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को रखा। राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने दो नवंबर को आयोजित रैली, भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय सम्मेलन, एआईएसएफ के राष्ट्रीय सम्मेलन और सितम्बर तक पार्टी के सभी शाखा और अंचल सम्मेलन आयोजित करने को लेकर रूपरेखा पेश की। राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार सिंह कार्य समीक्षा रिपोर्ट पेश की।

भाकपा महासचिव डी राजा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पराजित कर संविधान तथा लोकतंत्र की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने का आहवान किया। उन्होंने इस दिशा में 23 जून को पटना में आयोजित प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक को एक स्वागत योग्य कदम करार दिया। भाजपा शासन के नौ वर्षो में लोकतंत्र, संविधान और मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया है। संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बना दिया गया। केंद्र सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर कार्य कर रही है। देश में पूंजीवादी और सांप्रदायिक ताकतें एकजुट हो गयीं हैं। इन ताकतों को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से हटाना है। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई लोकतंत्र, संविधान तथा लोगों को बचाने और नया भारत बनाने के लिए लड़ी जायेगी। केंद्र सरकार संघीय ढांचे को खत्म कर रही है। लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर केंद्र से भाजपा को हटाना होगा। केंद्र सरकार सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रही है और फासीवाद के रास्ते पर बढ़ रही है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार गरीब और मजदूर विरोधी है। इस सरकार में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाना होगा।

बिहार की राजधानी पटना में भी हुई विपक्षी दलों की ऐतिहासिक बैठक का स्वागत करते हुए भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। केंद्र से मोदी सरकार को हटाने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता और एकता जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आमंत्रण पर विपक्षी दलों की एकजुटता से साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व गठबंधन की करारी हार होने वाली है। मोदी सरकार जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रही है, उससे संविधान खतरे में है। मौजूदा केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। बीते नौ साल में श्रमिकों, किसानों, बेरोजगारों और नौजवानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है।

बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव नागेंद्रनाथ ओझा दो नबम्बर को पटना में होने वाली भाजपा हटाओ, देश बचाओ रैली की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रैली की तैयारी के लिए अभी से ही गांव गांव बैठकों का दौर शुरू कर दी जाए।

बैठक में पदयात्रा तथा जनसत्याग्रह की समीक्षा की गई। पार्टी के राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती से 31 मई 2023 सक पदयात्रा तथा राज्य परिषद के निर्णयानुसार 08–09 जून 2023 को जिला मुख्यालयों पर आहुत जनसत्याग्रह का संक्षिप्त सूचनात्मक प्रतिवेदन रखा गया। राज्य परिषद के निर्णयानुसार शाखा तथा अंचल सम्मेलन को सितम्बर माह तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस संबंध में जिला परिषद की बैठक शीघ्र बुलाकर ठोस योजना बनायी जाएगी।

02 नवम्बर, 2023 को गाँधी मैदान, पटना में पार्टी की ओर से 'भाजपा हटाओ, देश बचाओ' आयोजित रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला से शाखा स्तर तक बैठकें आयोजित कर तैयारी शुरू की जाएगी।

उधर, 24 जून को राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आमंत्रण पर आहूत देश के प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक में मौजूद 15 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में भाग लेने और भाजपा–संघ मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया जो व्यापक राष्ट्रहित में लोकतंत्र व संविधान की हिफाजत के लिए एक स्वागतयोग्य प्रस्थान बिंदु है। आगे की बैठक, जो जुलाई के पहले पखवारे में शिमला में आयोजित होनी है उसमें राष्ट्रीय विपक्षी एकता की प्रक्रिया को नयी ऊंचाई देते हुए एक देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन (पीडीए) की सारी पूर्वापेक्षायें पूरी करते हुए उसे ठोस स्वरूप दिया जाना है ताकि आगामी चुनावों में मोदी की निरंकुश सत्ता को अपदस्थ करने के लिए एक के मुकाबले एक का चुनावी परिदृश्य तैयार किया जा सके।

डी राजा ने अपने संबोधन में बिहार की पूरी पार्टी और उसके नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई दी कि उसने उक्त विपक्षी समागम से पूर्व भाजपा हटाओ–देश बचाओ–नया भारत बनाओ के नारे के साथ राज्यव्यापी पदयात्रा अभियान चलाया और विगत 8, 9 और 20 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के समक्ष जनसत्याग्रह–जेल भरो अभियान चलाकर बदलाव की अनुकूल जमीन तैयार करने का काम किया जिसमें करीब डेढ़ से दो लाख लोगों की भागीदारी हुई और जगह–जगह हजारों लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई।

भाजपा हटाओ–देश बचाओ अभियान को आगे भी जारी रखते हुए भाकपा, की राज्यकारिणी ने व्यापक योजना बनायी जिसके तहत आगामी अगस्त–सितम्बर महीनों में पार्टी की शाखाओं और प्रखंड इकाइयों के सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे, बड़ी संख्या में सभी जिलों में आम सभायें की जायेंगी और 02 नवंबर को राजधानी पटना में पार्टी की ओर से एक विराट जन रैली की जायेगी। भाकपा महासचिव ने पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समेत उपस्थित सभी जिला मंत्रियों को साधुवाद देते हुए बिहार में पार्टी के बेहतर भविष्य की कामना की।

भाकपा महासचिव डी. राजा ने कहा कि फासीवादी ताकतों को देश की सत्ता से हटाने के लिए वाम लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष पार्टियां एकजुट हो गयी हैं। वाम लोतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष

शेष पेज 2 पर...

लोकतंत्र पर संकट

संपादकीय

नेपोलियन ने एक बार कहा था, ''.....पैसे की कोई मातृभूमि नहीं होती। पैसा लगाने वाले वित्त पूंजी के मालिकों में कोई देशभक्ति नहीं होती। इन सबका एकमात्र उद्देश्य होता है पाना, सबकुछ पा लेना।'' दीखता नहीं यह कभी, लेकिन वही यह पंथ है जहां वित्त पूंजी की जड़ें जमती हैं। हमारा देश क्रमशः बढ़ता जा रहा है पूंजीवाद के अतिविकसित अध्याय की ओर, जिसका कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन सारांश उसका है औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी का मिश्रण। जून 8, 2023 को घोषित हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में यह अनुमति कमर्शियल बैंकों को दे दी गई है कि वे उन विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के साथ समझौता कर सकती हैं जो कर्ज और ब्याज चुकाने की क्षमता रखने के बावजूद कुछ भी चुकाना नहीं चाहते। इस नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि अगर किसी ऐसे कर्ज न चुकाने वाले के ख़िलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिनमें उन्हें अपराधी का ही दर्जा दिया गया है, तो उस कार्रवाई को वे अवश्य पूरा कर लें, लेकिन साथ ही ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं पड़ने की सतर्कता बरतें ताकि न्यायिक कार्रवाई और उससे जुड़े खर्चों में उन्हें न पड़ना पड़े। पांच वर्षों के बाद ये सभी कर्जदार जिन्होंने स्वेच्छा से कर्ज वापस नहीं किया, उन सबको फिर से नया कर्जा दिया जा सकेगा। यह वित्त पूंजी के तर्क से पूरी तरह मेल खाता है, और इसलिये वित्त को एक ओर, जहां स्वामिभक्त सेवक माना जाता है, वहीं उन्हें निष्ठुर स्वामी भी माना जाता है।

आज हमारे पैरों के नीचे की जमीन में दरारें गहरी और चौड़ी होती जा रही हैं। वैश्विक स्तर पर इस असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है, और साथ ही कोशिश हो रही है कि संघीय ढांचे को पूरी तरह कुचल डाला जाय। इसके साथ ही कट्टर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और लगातार चुनौती दे रहा है संविधान के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी पहलुओं को। जनवाद के मूल आधार, जो टिके हैं हमारे जनवाद, संविधान और विचारों की स्वतंत्रता पर, उन पर दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया की तलवार लटक रही है। इसकी मज़बूत एकता और संघीय चरित्र, जो हमारी बहुआयामी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते है, उन पर भयानक आघात किया जा रहा है।

किसी भी क्षेत्रीय विकास की कोशिश या उसकी परिकल्पना तक को नष्ट कर दिया जाता है इसका एक उदाहरण है जीएसटी, जो राज्यों पर थोपा गया। लेकिन अलग–अलग चीजों के ऊपर उसी अनुसार कर तय करने का भी राज्यों को अधिकार नहीं दिया गया। पहले यह संवैधानिक अधिकार राज्यों के पास भी था, पर अब केंद्र ने उसे अपनी ज़द में कर लिया है। राज्यों को उतना ही देना पड़ेगा, जितना उनके लिये केंद्र तय करेगा जबकि जीएसटी कौंसिल राज्यों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करती है। यह यह सब राज्यों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में सीमित कर देता है। केंद्र पूरे देश पर अपना आधिपत्य रखता है। इस तरह संघीय ढांचा बिखरता जा रहा है, और साथ ही मझोले और छोटे उद्योगों और उनके मालिकों के लिये अंधकार सिर्फ वर्तमान में नहीं है, यह भविष्य को भी समेटे लिये जा रहा है। केंद्र राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को तो छीन ही चुका है, जिसके ज्वलंत उदाहरण हैं श्रम कानून को सिर्फ चार कोडों में सीमित करना, और तीनों कृषि कानून, जो बकायदा संसद में पारित हुए थे उन्हें ख़त्म करना। श्रम कानून में 29 श्रम क़ानून शामिल थे और इनमें हर एक के लिये जनता ने लंबे संघर्ष किए थे और सफलता पाई थी। ये श्रम क़ानून पहले समवर्ती सूची (कॉन्करेन्ट लिस्ट) में थे, राज्य और केंद्र दोनों के पास इसका अधिकार था। लेकिन अब केंद्र कॉरपोरेट सेक्टर को समर्थन देते हुए ''काम पर रखो, और हटाओ'', ठेके पर नौकरी, बढ़े हुए काम के घंटे और वेतन में भारी कटौती को लागू कर रहा हे। राज्यों को श्रम कोडों के अनुसार ही नियम बनाने के लिये मज़बूर किया जा रहा है, ताकि उन्हें व्यवहार में लाया जा सके। किसानों के क़ानूनों को तो उनके ऐतिहासिक धरने के बाद वापस लिया गया, लेकिन एमएसपी, जिसकी प्रमुख मांग थी, वह नहीं दिया गया।

संकट के समय राज्यों की जनता जब विवश होती है, उन्हें किसी तरह की कोई राहत केंद्र से नहीं मिलती। कल्याणकारी क़दमों के खर्च उठाने वाली राशि केंद्र द्वारा न सिर्फ देर से मिलती है, बल्कि अधिकतर राज्यों को आवश्यकतानुसार मिलती भी नहीं। योजनाएं देर से शुरू होती है, इनमें पैसा भी बहुत कम मिलता है, इसलिये कर्जदार होना भी अनिवार्य हो जाता है, और इसके बीच योजना को लागू करने के लिये जो फंड रहता है, वो या तो पड़ा ही रह जाता है या किसी दूसरे मद में चला जाता है। मनरेगा तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें कितने ही मजदूर केंद्र से फंड नहीं आने के कारण असहनीय तकलीफ में रहते रहे। फंड जो केंद्र से आना था, आया ही नहीं और मजदूर कर्ज में पड़ गए। केंद्र की दूसरी योजनाएं, जैसे शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, एससी और एसटी के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति का नहीं पहुंचना, शिशु और माता के स्वास्थ्य के लिये पोषक भोजन का खर्च, जो निश्चित तौर पर दिए जाने का नियम था, उन सब पर कुल्हाड़ी चला दी गई। राज्यों को उनके कल्याणकारी फंड से अलग रखना ही कारण बनता है उनकी आर्थिक स्थिति के अधिकतर खराब होने का। इससे वे दुर्बल से दुर्बलतर होते चले जाते हैं और केंद्र की सहायता पर ही निर्भर रहने लगते हैं।

इसी सब में आ जाता है हिन्दुत्ववादी विचार, जो तैय्यार करते हैं अल्ट्रा नेशनलिस्ट धारा, जिसमें संप्रदायवाद का उपयोग करते हुए सबकुछ ध्वस्त करने की भी तैय्यारी होती है। सांप्रदायिकता की इस सबमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इस सब में उद्देश्य जो स्पष्ट होकर आता है वह है एकता और बहुलता को ध्वंस करने कोशिश।

इस सबके बीच देशभक्ति को भी दुहराया जाता है एक मिथ की तरह और साथ ही युद्ध को भी बढ़ावा देने की कोशिश होती है। उसी सांस के साथ कोशिश होती है देश की सार्वभौमिकता और सुरक्षा को भी दांव पर लगा देने की, जब प्रतिरक्षा के उद्योगों का भी निजीकरण किया जाता है। विदेशी पूंजी को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। इस सबको डिफेंस के साथ ही जोड़ दिया जाता है, ताकि सबका क्षय हो। इसी सिलसिले में धारा 370 को उठाकर जम्मू और कश्मीर को दो राज्यों में बांट दिया जाता है। यही विभाजनकारी योजना निष्ठुरता के साथ अल्पमत के अधिकारों को हनन करने में भी उपयोग में आती है। यही विभाजन जनवादी संस्थानों को विघटित करने में भी उपयोग में आता है। जनवादी बनावट और संगठन को तोड़कर उसे मनमाने तरीके से, केंद्र के लिये, उनके समर्थकों को दायित्वपूर्ण पद देकर बिठाया जाता है। इससे उनके लिए अपनी विचारधारा लागू करना भी आसान हो जाता है। संघ की विचारधारा को अपनाकर यहां अपने समर्थकों को अध्यक्ष या ऐसे ही महत्वपूर्ण पदों पर बिठाते हैं।

इस तरह इन संस्थानों में मूल समस्या का हल इसी विचारधारा के अनुसार किया जाता है। यह विश्वविद्यालयों के विषयों, विभागों के अध्यक्ष हैं, विभिन्न कमीशनों और कौंसिल के अध्यक्ष होते हैं, साथ ही सरकारी एवं पुलिस फोर्स और सरकार के विभिन्न विभाग, जैसे सी.बी.आई., ई.डी. और अन्यों में भी नियोजित किए जाते हैं। यह सब सरकार का पूरी तरह सहयोग करने के लिये किया जाता है। हर उस जगह पर जहां पर यह वैचारिक प्रभाव सशक्त और सक्रिय रखता है, वहां यह न सिर्फ वर्तमान छीनता है, बल्कि अतीत भी और साथ ही संपूर्ण ऐतिहासिकता भी।

एआईएसएफ का 30वां ऑल इंडिया सम्मेलन बेगुसराय में

पटना , 4 जुलाई, 2023: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का 30वां राष्ट्रीय सम्मेलन 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक बेगुसराय में आयोजित होगा।

2 जुलाई को बेगुसराय के जीडी कालेज में 101 सदस्यीय स्वागत समिति का गठन किया गया, जिसका स्वागताध्यक्ष विधायक सह विधान सभा के भाकपा सचेतक रामरतन सिंह और स्वागत समिति के महासचिव एआईएसएफ के बिहार राज्य संयोजक अमीन हमजा चुने गए। बैठक में भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय, एआईएसएफ के राष्ट्रीय महासचिव विक्की माहेसरी, पूर्व महासचिव विजेंद्र केशरी, भाकपा के पूर्व राज्य सचिव राजेंद्र प्र. सिंह, पार्टी जिला सचिव अवधेश कु. राय, बखरी से पार्टी विधायक सह खेमयू बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष सूर्यकांत पासवान, जीडी कालेज के प्राचार्य डॉ. राम अवधेश कु. सिंह, वैली स्कूल के निदेशक डॉ. आर एन सिंह, प्रा. शिक्षक संघ के जिला सचिव श्री उमेश सिंह सहित बड़ी संख्यां में शिक्षाविद, छात्र–युवा तथा विभिन्न जन–आंदोलनों से जुड़े संघर्षकामी प्रबुद्ध लोग बैठक में शामिल हुए।

बाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एआईएसएफ के महासचिव विक्की माहेसरी ने सम्मेलन का ब्योरा पत्रकारों के साथ साझा किया। और देशभर से आने वाले चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में विस्तार से बाताया।

लोकतंत्र, संविधान और धर्मनिरपेक्षता...

पेज 1 से जारी...

पार्टियां पूरे देश में संयुक्त राजनीतिक अभियान चलायेगी और भाजपा सरकार की नीतियों का फंडाफोड़ किया जायेगा। भाजपा सरकार आरएसएस का एजेंडा देश पर थोपना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाकर संविधान, लोकतंत्र और समाज को बचाना है। भाकपा महासचिव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा राज्यों की राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जायेगा। बिहार में राजद, जदयू, भाकपा, माकपा, माले और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी तो तमिलनाडु में डीएमके, भाकपा, माकपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी। इसी तरह की रणनीति अन्य राज्यों में बनायी जायेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और केरल का दूसरा मामला है।

भाकपा राज्य सचिव ने रामनरेश पांडेय ने कहा कि भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत राज्य के जिला मुख्यालयों पर आठ, नौ और 20 जून को जन सत्याग्रह और जेल भरो अभियान चलाया गया। जिसमें डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों पार्टी साथियों और हमदर्दो की भागीदारी हुई। भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान को और तेज किया जाएगा। पटना में दो नबम्बर को भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली ऐतिहासिक साबित होगी। संवाददाता सम्मेलन में राज्य सचिव मंडल सदस्य रामबाबू कुमार व प्रमोद प्रभाकर और विधायक सूर्यकांत पासवान भी मौजूद थे।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन: एक अन्य जुमला

डॉ. सोमा मार्ला

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने को स्वीकृति दी है। 55 हजार करोड़ रुपए से वित्त पोषित (पांच वर्षों की अवधि में) इस स्कीम का उद्देश्य नवप्रवर्तन पर जोर देते हुए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों, आईआईटी, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना है। विवादास्पद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक हिस्से के तौर पर इसका कार्य, जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं की सेवा करने के बजाय बाजार एवं कारपोरेट तबके की खिदमत करने के लिए भारतीय विज्ञान की बुनियादों का पुनर्गठन करना है। संसद के आगामी मानसून सत्र में इसके लिए बिल प्रस्तावित है।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक एकल स्वीकृति अनुसंधान वित्त पोषक संस्था है और इसके फलस्वरूप पहले से ही काम कर रही कई वित्त पोषक एजेंसियां जैसे कि सीएसआईआर , डीएसटी, डीबीटी एवं अन्य बंद हो जाएंगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य फंडिंग का केंद्रीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भगवा विचारों के उद्देश्यों के अनुकूल फंड आवंटन करना है।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक ऐसे संकटपूर्ण समय में स्थापित किया जा रहा है जबकि भारतीय विज्ञान वित्तीय संकट और सामाजिक उद्देश्यों को, जो देश की स्वतंत्रता के बाद उसे सौंपे गए थे, कमजोर किया जा रहा है। अनेक आईआइटी और राष्ट्रीय संस्थान ऐसे हैं जो विश्व स्तरीय अनुसंधान करने के लिए जाने जाते रहे है और जिन्होंने टर्बाइन, हैवी बॉयल, पशु एवं मानव वैक्सीन (टीबी, कुष्ठ एवं अन्य रोगों के वैक्सीन) आदि का सफलतापूर्वक निर्माण किया। अब सरकार इन संस्थानों को वाहियात किस्म की बातों के संबंध में अनुसंधान करने के लिए कहती है और उन्हें पुराने जमाने के कथित पुष्पक विमानों, पंचगव्य, गोमूत्र या गोबर आदि जैसे विषयों पर अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जलजनित रोगों, टीबी जैसे संक्रामक रोगों, कुपोषण, इलेक्ट्रोनिक्स में आधारभूत अनुसंधान, माइक्रोचिप डवलपमेंट, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, स्वच्छ पेयजल एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अनुसंधान की उपेक्षा की जाती है और उनके लिए कम बजट आवंटन किया जाता है जिसका अर्थ इस के अलावा कुछ नहीं निकलता कि इन दिशाओं में अनुसंधान को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। पिछले कुछ समय से पुराण कथाओं में कही गई अवैज्ञानिक बातों का महिमामंडन किया जा रहा है और वैज्ञानिक नवप्रवर्तन एवं ज्ञान की उपेक्षा की जा रही है। विश्व की पांच में से चार सबसे बड़ी कंपनियां– एप्पल, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ज्ञान आधारित हैं; जब तक भारत में कृत्रिम मेधा, जीनोम सीक्वेन्सिग या क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ज्ञान के नए क्षेत्रों में अनुसंधान के कार्य को तेजी नहीं दी जाती, हम टेक्नोलॉजी बस में चढ़ने से वंचित रह जाएंगे और पश्चिम की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार बने रहेंगे।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर अनुसंधान एवं नव प्रवर्तन में निवेश 2008 के 0.84 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2018 में 0.69 प्रतिशत पर आ गया है, जब कि यह अमरीका में सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत, चीन में 4.1 प्रतिशत, इजरायल में 4.3 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका में 4.2 प्रतिशत है। भारत में आबादी के 15 लाख लोगों में अनुसंधानकर्ताओं की संख्या 15 है जबकि चीन में 111, अमरीका में 423 और इजरायल में 825 है। इसका सीधा नतीजा यह निकलता है कि पेटेंटों और पब्लिकेशनों में भारत बहुत पीछे रह जाता है। अनुसंधान कार्यों के लिए कम बजट आवंटन के कारण वैज्ञानिक समुदाय को मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। भारत में एक अन्य चुनौती यह है कि युवा वैज्ञानिकों को नियमित तौर पर वेतन भी नहीं मिलता और बहुस्तरीय नौकरशाही के कारण न तो सही फैसले लिए जाते हैं, न ही समय पर लिए जाते हैं। जो फैसले तुरंत लिए जाने चाहिए वे अत्यधिक देरी के बाद लिए जाते है। वैज्ञानिक संस्थानों के लिए समय पर फंड प्रदान नहीं किए जाते। मुझे व्यक्तिगत तौर पर अनुभव है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग या डीएसपी बड़ी मात्रा में फंड को समय पर न देकर उस समय देते है।

इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बॉडी (डब्ल्यूआईपीओ) के अनुसार, चीन ने 1,538 मिलियन पेटेंट, अमरीका ने 605,571 पेटेंट हासिल किए जब कि भारत ने मात्र 45, 057। हमें गर्व है कि आज वैज्ञानिक लेखों के प्रकाशन के संबंध में भारत पांचवां सबसे बड़ा प्रकाशक है। परंतु इनमें से 80 प्रतिशत लेख बिना विद्वत समीक्षा के होते हैं और उनका प्रकाशन विश्व में मान्यता प्राप्त पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं होते।

हाल में कोविड महामारी फैलने के कारण सरकार ने वैज्ञानिक समुदाय की चेतावनियों की उपेक्षा की और वैज्ञानिक सोच से काम लेने की बजाय कुंभ मेले जैसे बड़ी भीड़भाड़ वाले उत्सवों को प्रात्साहन दिया और थाली बजाने, दीए जलाने, गोमूत्र का प्रयोग करने और ऐसी देसी दवाओं और नुस्खों को प्रोत्साहन दिया जो क्लीनिकली टेस्टिड नहीं हैं। जब इस तरह की टोटकेबाजी का विरोध होने लगा और वैज्ञानिक समुदाय ने ऐसी बातों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आवाज उठाई तब कहीं जाकर सरकार की नींद खुली और कोविड की दवाईयों एवं वैक्सीनों के आयात और घरेलू स्तर पर वैक्सीन डवलप करने और बनाने की तरफ ध्यान गया; विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत एक जीनोम बॉडी आईएनएसएसीओजी बनाया गया, देशभर में उसकी शाखाएं खोली गई; जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पीसीआर टेस्टिंग शुरू की गई; महामारी के नियंत्रण के लिए वायरल वेरियेन्ट्स की मॉनटरिंग शुरू की गई। महामारी को कंट्रोल करने के लिए आईएनएसएसीओजी के वैज्ञानिकों ने तेजी से सीक्वेंसिंग और समय–समय पर वेरियेन्ट्स की पहचान की दिशा में जबर्दस्त योगदान दिया जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं।

केंद्र ने विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्री ने एक अन्य वायदा यह किया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों एवं राज्यों के कॉलेजों में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा। परंतु जब हम देखते है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के तौर पर कम बजट आवंटन हो रहा है, पाठ्यक्रमों से डार्विन के सिद्धांत, पीरियोडिक टेबल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों को हटाया जा रहा है तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्लासरूम में अनुसंधान को प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है। बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों को पाठ्यक्रमों से हटाकर छात्रों में न तो साइंटिफिक टेम्पर पैदा किया जा सकता है और न उन्हें विज्ञान एवं अनुसंधान की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि नॉलिज इकोनॉमी (ज्ञान अर्थव्यवस्था) में आगामी समय में करोड़ों रोजगार पैदा होंगे। परंतु जब छात्रों में अवैज्ञानिक एवं कल्पित मिथकों एवं पुराण कथाओं के प्रति आकर्षण पैदा करने और उन्हें विश्वसनीय साबित करने की फर्जी बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है तो क्या ये छात्र नॉलिज इकोनॉमी के संभावित फायदों से वंचित नहीं रह जाएंगे?

समग्र औद्योगीकरण एवं कृषि विकास के लिए वैज्ञानिक टेम्पर के साथ विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्र भारत में 1980 के मध्य दशक तक यानी नव उदारवाद के प्रारंभ तक समझा जाता था कि स्वतंत्र विकास के लिए विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की अत्यधिक आवश्यकता है और इन चीजों को पश्चिम से खरीदा नहीं जा सकता; अतः हमें स्वदेशी तौर पर अपनी क्षमताएं बढ़ाने की जरूरत है। इस सोच और नीति के फलस्वरूप अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, रक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे कि सीएसआईआर, आईसीएआर खड़े किए गए, आईआईटी स्थापित किए गए और विश्वविद्यालयों में विज्ञान को प्रोत्साहन दिया गया।

ज्ञान और मशीनरी का आयात कर ''मेक इन इंडिया'' के अंतर्गत कोई सामान बना लेने से भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने में मदद नहीं मिलती। भारत एक बड़ा और अच्छा बाजार है। अतः स्वाभाविक है कि पश्चिम की बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारी नीतियों को प्रभावित करने में अत्यंत दिलचस्पी लेती हैं। स्वतंत्रता के पहले दशकों में पश्चिम के देशों ने भारत को औद्योगिक विकास में मदद देने से इंकार कर दिया था। केवल सोवियत संघ ही था जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मदद की और इस्पात, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा एवं फार्मास्युटिकल्स जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम खड़े करने में भारत का सहयोग किया। रिलायंस, मित्तल और आज के अन्य बड़े उद्योग इसलिए खड़े हो सके कि ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएचईएल जैसे सार्वजनिक संस्थान उनके विकास में मददगार बने। परंतु पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के इन संस्थानों को इरादतन कमजोर किया जा रहा है। जिसका नतीजा यह है कि बीएचईएल जो 1990 के दशक तक दुनिया के प्रमुख पावर प्लांट सप्लायरों में था, आज वह दक्षिण कोरिया और चीन की कंपनियों के सामने कमजोर पड़ गया है।

प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर विज्ञान के स्थान पर अन्य पर निर्भर अनुसंधान को लाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हुए आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की नीति के पीछे इरादा यह है कि सरकारी पैसे से चलने वाले अनुसंधान कार्य को कॉरपोरेट बिजनेस हितों की खिदमत के लिए निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए। पांच वर्षों के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए जिन 50 हजार करोड़ रुपए की बात की जा रही है उनमें 10 हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने से और बाकी 40 हजार करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आएंगे। आम जानकारी की बात है कि निजी क्षेत्र रिसर्च एंड डवलपमेंट में दिलचस्पी नहीं लेता, न उसे देसी स्तर पर कोई उल्लेखनीय क्षमता विकसित करने में दिलचस्पी है और वैज्ञानिक अनुसंधान में जो खर्च आता है उसमें निजी क्षेत्र का योगदान नाममात्र का है। निजी क्षेत्र कार, मोबाईल फोन एवं अन्य सामानों के निर्माण के लिए पश्चिमी की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रेडीमेड टेक्नोलॉजी के आयात को तरजीह देता है। परंतु पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, दवा उत्पादन, ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान के फायदे उठाने के लिए तत्पर रहता है। यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में ही हुआ कि पांच आईआईटी खड़े किए गए; बीएआरसी, इसरो, नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री, नेशनल स्टेटिस्टिकल इंस्टीच्युट जैसे राष्ट्रीय अनुसंधान अस्तित्व में आए और इंडियन कौंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जैसे संस्थान विकसित हुए।

आरएसएस शुरू से ही आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास के लिए पंचयोजनाओं का खुलकर विरोध करता रहा है। यही कारण है कि मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के अपने मुहावरे और ''मेक इन इंडिया'' को आत्मनिर्भरता समझती है। मशीनरी के आयात और मोबाइल, ऑटो मोबाइल एवं अन्य तमाम सामानों के उत्पादन के लिए पश्चिम की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्पेयर पॉर्ट्स और ट्रान्सफर्ड टेक्नोलॉजी का अर्थ आत्मनिर्भरता नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ही देश में विकसित टेक्नोलॉजी, मशीनरी एवं सामानों का उत्पादन। सभी सामानों का उत्पादन देश में ही होना चाहिए जिससे देश के युवाओं के लिए रोजगार पैदा हो। आरएसएस की सोच का लक्ष्य देश के अंदर विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के विकास को प्रोत्साहन न देते हुए लोगों को प्राचीनकाल की वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गरिमा के मिथक के वशीभूत कर प्रश्न करने की प्रवृत्ति, तर्क एवं विज्ञान को कुचलना और भारत के विशाल बाजार को भारतीय और बहुराष्ट्रीय निगमों के सामने आत्मसमर्पण करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्वीकृति दी है वह अनुसंधान इकोसिस्टम में सुधार नहीं कर सकता। यह फैसला आत्मनिर्भर वैज्ञानिक अनुसंधान को देशी और विदेशी निगमों पर निर्भर बनाता है जो देश के स्वतंत्र विकास और जनता के कल्याण के लिए घातक है।

श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी को भाकपा की बधाई

भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य डॉ. के. नारायणा के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दो सदस्यीय प्रतिनिधि दल श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएसएल) की स्थापना के 80वीं सालगिरह समारोह में सम्मिलित हुआ। प्रतिनिधि दल के दूसरे सदस्य भाकपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य टी.राममूर्ति हैं। सथापना दिवस के 80वें स्थापना दिवस समारोह के लिए भाकपा बधाई संदेश का पाठ इस प्रकार है:

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की ओर से श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी की 80वें स्थापना दिवस समारोह में मौजूद पार्टी के नेतृत्व को और सभी सहभागियों को हमारा हार्दिक बिरादराना बधाई संदेश देने की अनुमति दे।

श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से ही इसके क्रांतिकारी इतिहास को हम अच्छे से जानते हैं। श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीलंका की आजादी की लड़ाई के लिए लोगों को लामबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संबंध में श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संगठित 1945, 1946 और 1947 की आम हड़ताल श्रीलंका के मजदूर आंदोलन में लिखी जाएगी।

तमिल भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल किए जाने के लिए, श्रीलंका के राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक समाधान के लिए और श्रीलंका के तमिल लोगों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के मानव अधिकारों और अन्य सामाजिक अधिकारों के लिए श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका भी हमें याद है।

प्रिय साथियों, आपकी पार्टी का स्थापना वर्ष समारोह एक ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब वित्तीय पूंजी की आक्रामक भूमिका और अमरीका, यूरोपीय यूनियन व नाटो धमकियों की नीति, प्रतिबंध और दबाव लगातार जारी हैं और वर्तमान में रूस–यूक्रेन संघर्ष की आड़ में रूस की घेरेबंदी कर रहे हैं, इस तरह से यूरोप और दुनियाभर में अमन और स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं।

अमरीकी साम्राज्यवाद एशिया–प्रशांत महासागर क्षेत्र में, दबदबा बनाने के लिए एक एशियाई नाटो बनाना चाहता है और इस क्षेत्र के कई देशों के साथ ओकस (एयूकेयूएस) क्वाड (क्यूयूएडी) और कई अन्य सैन्य संधियों के माध्यम से अस्थिरता पैदा करना चाहता है। इस तरह से यह इस क्षेत्र में दूसरी बड़ी शक्तियों को ऐसा करने के लिए उकसा रहा है खासतौर से हिंद महासागर के तटीय और पृष्ठीय देशों में, इस प्रकार हिंद महासागर क्षेत्र में हथियारों की होड़ को बढ़ा रहा है। खाड़ी और अरब देश के शासकों का नस्लवादी इजरायल के साथ नया गठबंधन मध्य–एशिया की पहले से ही अस्थिर परिस्थिति के लिए चिंताजनक भी है और यह फिलिस्तीनी जनता के जीवन को, इस क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। इस तरह की उभरती परिस्थिति में कम्युनिस्ट, वाम और अन्य जनतांत्रिक पार्टियों के बीच सहयोग सर्वोपरि है। साम्राज्यवादी चालों के खिलाफ, विदेशी सैनिक अड्डों के खिलाफ लड़ने और जनवादी मूल्यों के व्यापक प्रसार, जनवादी और मानव अधिकारों के लिए हमें अपनी गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। हमें मांग करनी चाहिए कि ''हिन्द महासागर अमन का क्षेत्र होना चाहिए''।

प्यारे साथियों, मुझे विश्वास है कि स्थापना दिवस का 80वां सालगिरह श्रीलंका के क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव के लिए मौजूदा आंदोलनों को आगे बढ़ाने के समस्त पार्टी सदस्यों के संकल्प को और मजबूत करेगा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बिरादराना संबंध जिंदाबाद!

बेरोजगारी भत्ते के लिए एआईवायएफ कनार्टक का राज्यव्यापी प्रदर्शन

बेगलुरू: हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के लोगों को पांच गारंटी दी। गारंटियों में से एक राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी वजीफा प्रदान करना है। यह वादा किया गया था कि बेरोजगार स्नातक और डिप्लोमा धारकों को क्रमशः 3000 और 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बेरोजगारी ही एकमात्र मापदंड बताया गया था।

चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। अब, यह कहा गया है कि 2022 में अपने संबंधित पाठ्यक्रम पूरा करने वाले स्नातक और डिप्लोमा धारकों को ही बेरोजगारी वजीफा दिया जाएगा।

एआईवाईएफ कर्नाटक राज्य परिषद ने राज्य सरकार से 2018 से बेरोजगार युवाओं को इसके लिए पात्र मानने की मांग करते हुए राज्य भर में प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया।

एआईवाईएफ ने रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और तत्कालीन भाजपा सरकार के तहत वर्षों पहले तैयार की गई राज्य युवा नीति में बदलाव की भी मांग की।

एआईवाईएफ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश बाला ने अमित कुमार, शांतराज जैन, वाणीश्री और अन्य के साथ बेंगलुरु में आयोजित प्रदर्शन में भाग लिया। एआईवाईएफ के राज्य सचिव एच.एम. संतोष ने गिरीश और अन्य लोगों के साथ हासन में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दावणगेरे, बेल्लारी, मैंगलोर, हरपनहल्ली, मोलाकलमुरु, हुविनहादुगली सहित विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन हुए। एआईवाईएफ के साथियों ने बड़ी संख्या में राज्य भर में प्रदर्शनों में भाग लिया।

खरीफ बुआई में किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिले खाद

पटना, 05 जुलाई 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने केंद्र सरकार से खरीफ मौसम में बिहार को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। बिहार में मानसून के सक्रिय होने से लगातार बारिश हो रही है और राज्य के कई हिस्सों में धान की रोपनी शुरू है। केन्द्र और राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित मूल्य पर डीएपी, पोटास, यूरिया, जिंक सहित खरीफ फसल की बुआई में उपयोग आनेवाले अन्य सामानों को उपलब्ध कराने की गारंटी करे।

भाकपा राज्य सचिव ने बयान जारी कर कहा कि गत वर्ष खरीफ मौसम और इस साल रबी की बोआई के समय में बिहार के किसानों को खाद नहीं मिल पाई थी। जिस कारण खेती प्रभावित हुई और किसानों को ऊंची कीमत पर खाद खरीदना पड़ा। खरीफ मौसम में खाद में कोई कमी नहीं हो इसलिए सरकार अभी से मुश्तैद रहे।

उन्होंने राज्य सरकार से खाद की कालाबजारी पर रोक लगाने की मांग की ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद मिल सके।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि खाद विक्रेताओं द्वारा डीएपी की ऊंची कीमत वसूली जा रही है। बाजार में अभी डीएपी 1700 रुपये प्रति बोरी की दर से बिक्री की जा रही है जबकि अधिकतम कीमत प्रति बोरी 1350 रुपये निर्धारित है। इसी तरह अन्य खाद की भी निर्धारित कीमत से अधिक की वसूली की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से लगातार छापेमारी अभियान चलाकर खाद की कालाबजारी पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की लेट लतीफे के कारण बिहार के किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाता है। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है।

उन्होंने केंद्र सरकार से ससमय बिहार को आवश्यकता के अनुसार खाद की आपूर्ति हो इसकी गारंटी करने की मांग की है।

इतिहास मिटाने के लिए नहीं, याद रखने के लिए है

जस्टिस आर.एन. चौहान
(सेवानिवृत)

प्रत्येक पीढ़ी को इतिहास की विवचेना का अधिकार है। जर्मन दार्शनिक, लेखक, सामाजिक वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने भी हमें याद दिलाया, ''इतिहास स्वयं को दोहराता हैः पहले एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में'' इसलिए इतिहास के सबक हमें अतीत की भूलों को न दोहराने का रास्ता दिखाते हैं।

इसलिए इतिहास लेखन कई बदलावों से गुजरा है। पश्चिमी इतिहासकार इतिहास को एक क्रमिक विकास में देखते हैं–जिसमें इंसान गुफा से लेकर उत्तर आधुनिक तक पहुंचा। अतः पश्चिमी इतिहासकारों के अनुसार इतिहास को एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की उत्तरोत्तर यात्रा है।

दूसरे इतिहासकारों ने इस वृतांत पर शंका कीः उन्होंने कहा मिस्र, रोमन, माया और एजटेक जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का पतन हुआ है। कुछ अन्य इतिहासकारों ने इतिहास में गिरने–उठने की बात कही है जैसे कि शक्तिशाली रोमन साम्राज्य से लेकर अंधकार युग कई इतिहासकारों ने इतिहास को राजवंशों, राजाओं, रानियों और साम्राटों की एक लड़ी के रूप में देखा है। यह इतिहास पढ़ाने का सबसे प्रचलित रूप है–पुरी तरह से व्यक्तियों, तिथियों और घटनाओं का वर्णन।

मार्क्सवादी इतिहासकार इतिहास को ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। उनके लिए, व्यक्ति इतिहास की दिशा को नहीं बदलते; आंदोलन इतिहास की दिशा को बदलते हैं।

इस तरह के इतिहास में मिस्र के विशाल पिरामिडों और फराओं का महत्व नहीं था। उसमें जो महत्वपूर्ण था कि वे लोग कौन थे जिन्होंने पिरामिड बनाए; तकनीक, विज्ञान और गणितीय सुनिश्चितता के आधार पर प्राचीन दुनिया की अद्भुत वस्तुएं बनाईं।

तथापि, इतिहास की विवेचना करना एक बात है और पाठ्यपुस्तकों से इसे मिटाना दूसरी बात है।

एनसीईआरटी ने हाल ही में माध्यमिक और उच्च कक्षा के छात्रों के लिए नई पाठ्य पुस्तकें जारी की हैं। इन पाठ्य पुस्तकों के नए संस्करण में भुगत इतिहास पर अध्यायों को हटा दिया गया है; इसने विवाद खड़ा कर दिया है। यहां यह मुद्दा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की विषयवस्तु में बदलाव के लिए सक्षम है कि नहीं, यहां मुद्दा हमारे इतिहास से इस तरह से अध्यायों की कांट–छांट से है–एक इतिहास जो न केवल शानदार है, लेकिन जो जारी भी है।

हमारे इतिहास के भागों को छिपाने से पहले एनसीईआरटी ने कुछ जरूरी सवालों को पूछा होता– हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं? हमारे इतिहास के भागों को मिटाने के परिणाम क्या होंगे? क्या जानबूझ इतिहास के संबंध में पैदा की गई दूरी हमारे नागरिकों को प्रबुद्ध करेगी? क्या इतिहास के किसी खास भाग को हटाने से हमारा देश मजबूत या कमजोर होगा? यदि सरकार का लक्ष्य ''सबका साथ, सबका विकास'' सुनिश्चित करने के लिए देश को मजबूत करना है, तब हमारे इतिहास में कांट–छांट आत्मघाती सुझाव है।

इतिहास छात्रों पर बोझ डालने के लिए नहीं बल्कि उन्हें प्रबुद्ध करने के लिए पढ़ाया जाता है। सर्वप्रथम, यह जानना जरूरी है कि हम कहां से आएं हैं। मनुष्य केवल भविष्य की ओर ही नहीं देखता वह अतीत की ओर भी देखता है। जमाइका के राजनीतिक कार्यकर्ता मार्कस गार्वे ने कहा कि ''अपने अतीत के इतिहास उद्भव और संस्कृतियों से अनजान कोई व्यक्ति वैसे ही है जैसे कि कोई पेड़ बिना जड़ के।''

बच्चों को मुकदमों और अभियोगों के बारे में जानना, और हमारे अतीत की सफलताओं को जानना जरूरी है। हम कहां से आए? हम एक मनुष्य के रूप में, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में कैसे विकसित हुए? हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ब्रितानी नेता, सिपाही और लेखक सर विस्टन चर्चिल ने ठीक ही कहा कि, ''अतीत में पीछे जितना देख सकते हो उतना ही भविष्य की ओर आगे देख सकते हों, ''इसलिए इतिहास का ज्ञान हमें एक टाइम कैप्सूल में रखता है।

दूसरा, यह हमें हमारे देश और संस्कृति के बारे में सिखाता है। जाति व्यवस्था कहां से आई? सनातन धर्म किस प्रकार बढ़ा हुआ? भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ। उत्तर और दक्षिण भारत इतने अलग क्यों हैं। भारत में विभिन्न भाषाओं के उद्गम क्या हैं।

विभिन्न समुदाय जैसे कि मुसलमान, पारसी, और इसाई कहां से आए। कैसे और कब जैनवाद और सिखवाद उभरे? देश में विभिन्न रिवाज क्या है? देश में इन रिवाजों के पैदा होने के कारण क्या हैं।

समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, दर्शन, कला, साहित्य, भाषा विज्ञान में इतिहास दौड़ता है। यह हमें बताता है कि हम कौन है और हम जिस तरह हैं वैसे क्यों हैं।

तीसरी बात, इतिहास अतीत की गलतियों और दुर्घटनाओं के बारे में बताता है। हम होलोकास्ट की दहशत के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु बम के विनाश के बारे में बढ़ते हैं। जैसे कि स्पेनी–अमरीकी दार्शनिक, निबंधकार, कवि और उपन्यासकार जार्ज सांतयाना ने कहा कि, ''जो अतीत को याद नहीं रख सकते वे दोबारा दोहराने के लिए अभिशप्त हैं।''

चौथी बात, इतिहास हमें अपनी आस–पास की दुनिया के बारे में बहुविधता के बारे में बताता है। यह हमें विभिन्न संस्कृतियों और समस्याओं, विभिन्न सरोकारों और विभिन्न सुझावों के बारे में बताता है; यह उन कारणों को बताता है कि लोग जैसे है वैसे क्यों है, हम ग्रीक और रोमन सभयताओं के बारे में, उनकी वक्तृता और वैज्ञानिक मनोवृति पर जोर के बारे में, उनके दुःखांत नाटकों और जनतांत्रिक नगरीय राज्य के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से विभिनन तरह के लोगों ने अपने समाज की विधवाओं की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। जहां इसाई जगत ने अपनी विधवाओं को ननरी (सन्यासिनी मठ) का रास्ता दिखाया तो इस्लाम जगत में उन्हें पुर्नविवाह की इजाजत मिली; हमने विधवाओं को सती (मृत पति के साथ जिंदा जलाना) किया, या मंदिरों वालों शहर (जैसे मथुरा) में रहना नियुक्त किया। एक सी रूप में मानवीय समस्याएं विभिनन समय और स्थानों में विभिन्न रूपों में दिखती है। फिर से इतिहास की पुर्नकल्पना के स्थान पर, हम दूसरों की खोजों, उपायों से सीखते हैं।

पांचवीं बात, इतिहास हमारी विश्वदृष्टि को खोलता है, हम दूसरी संस्कृतियों के बारे में, उनके सामाजिक मूल्यों के बारे में, उनकी जीवनशैली के बारे में अधिक ग्रहणशील होते हैं, जैसे ही हमें यह याद करेंगे कि इस्लाम अरब के रेगीस्तानी इलाके में पैदा हुआ था, तब हम खास इस्लामिक रिवाजों जैसे कि एक साथ खाना खाने को अच्छा मानेंगे–पानी को कभी उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग–अलग बर्तन की इजाजत नहीं देती; हरे रंग के लिए उनका प्यार–रेगिस्तान में हरा जीवन का प्रतीक हैं; बगीचों में फव्वारों और बहते पानी से उनका प्यार–सानी जीवन था, पानी स्वर्ग था।

छठी बात, इतिहास का अध्ययन एक तथ्य को अलग–अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत तैयार करता है। एक ही तथ्य की अलग–अलग विवेचना हो सकती हैः उत्तर भारत में 1857 की घटना को अंग्रेजों द्वारा 'विद्रोह' कहा जाता है। तब भी, हमारे लिए, यह ''आजादी की पहली लड़ाई'' है। विद्रोही अचानक स्वतंत्रता सेनानी हो जाते हैं, उसी तरह से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी–अमरीकी द्वन्द्व के दो विभिन्न और विपरीत विचेनाएं हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि कोई अमरीकी नजरिये से इतिहास पढ़ रहा है या जापानी नजरिये से। इतिहास इस तरह से छात्रों में विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक क्षमता विकसित करता है।

सातवीं बात यह है कि इतिहास मानव चरित्र को प्रकाश में लाता है; बताता है कि वह अच्छा है, बुरा है या कुरूप है; बहादुर है या कायर है; मेहनती है या कामचोर है। इतिहास में हमें यहां–वहां घूमते हुए तपस्वी और धार्मिक शिक्षक मिलते हैं–गौतम बुद्ध जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की; जैनवाद के 24वें तीर्थकर महावीर; सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानकदेव और हिन्दू सन्यासी, दार्शनिक, लेखक एवं धार्मिक शिक्षक स्वामी विवेकानन्द। हम ऑस्ट्रिया में जन्मे जर्मन के डिक्टेटर हिटलर के बारे सीखते हैं और सोवियत राजनीतिज्ञ, राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता एवं क्रांतिकारी वी.आई. लेनिन के बारे में भी सीखते हैं। हम तुर्क बादशाह सुलेमान, तेजस्वी, की बुद्धिमत्ता, कापिकाजे पायलटों की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं और फौजी सिपहसलार मीर जाफर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब बना, की कायरता को धिक्कारते हैं। जैसा कि एंथेस के इतिहासकार एवं जनरल थुसाइडिडेस ने कहा, ''इतिहास उदाहरण द्वारा दर्शनशास्त्र का शिक्षण है''।

आठवीं बात यह है कि इतिहास, सचमुच ही, हमें जीवन का दर्शन प्रदान करता है। युद्धों और खून–खराबे के बावजूद, दुर्भिक्ष और महामारियों के बावजूद, प्राकृतिक आपदाओं और कठिनाइयों के बावजूद मानवजाति का हजारों वर्षो से अस्तित्व बना रहा। इससे हमें आशा एवं अनुभव, ज्ञान एवं दृष्टि मिलती है। इतिहास में हमें जो असंख्य चरित्र मिलते हैं उनसे हम जीवन के बारे में सीखते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा, ''जब मैं निराश होता हूं तो मैं याद करता हूं कि इतिहास के तमाम दौर में सच और प्यार की हमेशा जीत होती है। इतिहास में अत्याचारी और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय तो लगता है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, परंतु अंत में वे सब धराशायी हुए–इसके बारे में हमेशा सोचें।

नौवीं बात यह है कि इतिहास किसी व्यक्ति एवं समाज में विश्वास जगाता है। अतीत की उपलब्धियों और सफलताओं के बारे में जानकर हमारी आत्म–पहचान की भावना मजबूत होती है। जापान में बच्चों को सिखाया जाता है कि वे सूर्य देवता के वंशज हैं और समुराई संस्कृति के उत्तराधिकारी है। जब दूसरे विश्वयुद्ध में जापान हार गया और एक संवाददाता ने एक जापानी व्यक्ति से पूछा कि अमरीका ने आपको हरा दिया है, आपको कैसा लग रहा है। उसने कहा, ''हमें बीस साल दीजिए, और हम अमरीकियों को हरा देंगे''। बीस साल के अंदर जापान की अर्थव्यवस्था अमरीका से आगे निकल गई। दुर्भाग्य से, हम अपने बच्चों को यह नहीं पढ़ाते कि भले ही हम एक युवा राष्ट्र हों, परंतु हम इस पृथ्वी की सबसे पुरानी सभ्यता हैं।

अंतिम बात यह है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति अच्छे नागरिक बनते हैं। वे अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पर गर्व करते है। क्योंकि राष्ट्रीय गर्व की भावना का अभाव है, हम लोग फिजूल का रोना रोते रहते हैं। हम नहीं सराहना करते कि पिछले 75 सालों में भारत ने बड़े कदम उठाए हैं, अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं; हम मानव द्वेषी और निराशावादियों का देश बन जाते हैं। एक व्यक्ति की तरह, यदि कोई देश आशा और दृष्टि खो दे तो वह साधारण से ऊपर कभी नहीं उठ सकता।

दुर्भाग्य से इतिहास को हटाने, या उसके एक हिस्से को हटाने से बच्चे उस विषय को पढ़ने के तमाम फायदों से वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा, यदि एक समुदाय विशेष का इतिहास हटाया जाता है तो उसके खतरनाक नतीजे निकलते हैं। वह समुदाय दिशाहीन हो जाता है, संबंध–भावना विहीन हो जाता है। वह महसूस करेगा उसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है।

इसके अलावा समुदाय विशेष के

शेष पेज 6 पर...

फतेहपुर खेत मजूदर यूनियन का जिला सम्मेलन संपन्न

खागा (फतेहपुर): उ.प्र. खेत मजदूर यूनियन जिला कौन्सिल फतेहपुर का 14वां जिला सम्मेलन– यूनियन के जिलाध्यक्ष सुमन सिंह चौहान की अध्यक्षता में खागा के गौरव मैरिज हॉल में दिनांक 30 जून 2023 को सम्पन्न हुआ। जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में उ.प्र. खेत मजदूर यूनियन के महामंत्री फूलचन्द्र यादव मौजूद रहे।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए फूलचन्द्र यादव ने आज की मौजूदा परिस्थिति में देश और दुनिया के अन्दर की तमाम घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्दर अमेरिकी साम्राज्यवाद अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए तरह–तरह के हथकण्डे अपना रहा है। अपने यहाँ तैयार हथियारों की बिक्री करने के लिए एक देश से दूसरे देश को लड़ाने का काम कर रहा है। अपनी अध्यक्षता वाले नाटो संगठन का तमाम देशों के खिलाफ गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। इराक, अफगानिस्तान, यूरोप, वियतनाम, क्यूबा समेत तमाम उदाहरण दुनिया के सामने मौजूद है जहाँ पर अमेरिका ने बेवजह अपनी दादागीरी दिखाते हुए उन देशों को बर्बाद किया है। अब उसका नया निशाना ताइवान व ईरान है जहाँ अपनी सैन्य गतिविधियों के माध्यम से उनके पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के लिए उकसावे का कार्य कर रहा है। अमेरिका की निगाह पूरी तरह से भारत के बाजारों पर है। तमाम तिकड़मे करके दुनिया के सबसे बड़े भारत के बाजार को अपने कब्जे में करना चाहता है। देश की मोदी सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने नतमस्तक है और विदेशी निवेश के लिए तमाम विदेशी बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में आमंत्रित किया जा रहा है। मोदी सरकार देश के अन्दर एक दलीय संसदीय प्रणाली को लागू करने के लिए धार्मिक व साम्प्रदायिक एजेण्डे पर काम कर रही है। भारतीय संविधान को खत्म करे मनुस्मृति पर आधारित सत्ता कायम कराना चाहती है। लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए देश की 87 प्रतिशत आबादी को संघर्ष करना होगा। यादव ने आगे कहा कि मोदी सरकार पूरी बेशर्मी के साथ निजीकरण के रास्ते पर चल रही है। देश के द्वारा 70 सालों में अर्जित की गयी सम्पत्ति को औने–पौने दामों में अपने मित्र उद्योगपतियों को बेच रही है। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से जो मीडिया के रूप में है, पूरी तरह से सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है। ऐसी स्थिति में लाल झण्डे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसमें खेत मजदूरों का संघर्ष अति महत्वपूर्ण है।

सम्मेलन को संबोधित करते करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य मंत्री परिषद के सदस्य मोतीलाल ने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार लोकतंत्र के बुनियादी स्वरूप पर हमला कर रही है तथा जातीय व धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रही है। यूनियन के जिला महामंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने संगठन के पिछले क्रिया कलापों संगठनात्मक स्थिति और राजनैतिक रिपोर्ट पेश की, जिस पर 10 प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किये चर्चा के बाद कुछ सुझावों को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट सर्वसम्मति से पास की गयी। सम्मेलन के अन्त में 15 सदस्यीय जिला कौन्सिल का चुनाव किया गया, जिसके सुमन सिंह चौहान अध्यक्ष, राजेन्द्र चन्द्रशेखर सिंह उपाध्यक्ष, रामकृष्ण हेगड़े जिला महामंत्री, कयामुद्दीन व मूलचन्द्र मंत्री एवं हरिश्चन्द्र को कोषाध्यक्ष चुना गया।

सम्मेलन का समापन करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री फूलचन्द पाल ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी साथियों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने सम्मेलन के माध्यम से मनरेगा में 600/रू दैनिक मजदूरी व 200 दिन का काम 55 वर्ष के खेत मजदूरों को 5000/रू मासिक पेंशन, खेत मजदूरों को सामाजिक न्याय एवं सामाजिक पेंशन की माँग का प्रस्ताव रखा।

सम्मेलन की शुरुआत उ.प्र. खेत मजदूर यूनियन के झण्डे को वरिष्ठ साथी रामऔतार सिंह के द्वारा झण्डोत्तोलन करके हुई। झण्डोतोलन के बाद रामचन्द्र द्वारा झण्डा गीत प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन को रामप्रकाश, रामचन्द्र, चन्द्रशेखर सिंह, रामऔतार सिंह आदि लोगों ने सम्बोधित किया और अपनी शुभकामनाएं दी।

इतिहास मिटाने के लिए नहीं, याद रखने के लिए...

पेज 5 से जारी...

इतिहास को हटाने से उसकी पहचान खत्म होती है। बड़ी आसानी से बहुसंख्यक समुदाय को विश्वास कराया जा सकता है कि समुदाय विशेष महत्वहीन एवं उपेक्षणीय है। इसका परिणाम बहुसंख्यकों के अत्याचार के रूप में निकलेगा और अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप में सिमटने लगेगा। ऐसी हालत में में अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित एवं भयभीत अनुभव करता है। इस तरह के विभाजन का नतीजा दो समुदायों के बीच झगड़ों के रूप में निकलता है। इस तरह की अशांति और झगड़े से मजबूत होने के बजाय देश कमजोर होगा।

इसके अलावा हम अपने इतिहास की गलतियों को दोहराते रहते हैं।

यह एक गलत समझ है कि अंग्रेजों ने ''फूट डालो और राज करो'' की नीति का पालन किया। असल में, हमारे इतिहास में हमेशा, यूनानी हमले से लेकर 1962 में चीनी हमले तक, हमारे ऊपर दूसरों ने जीत हासिल की क्योंकि हम हमेशा बंटे हुए थे। जर्मन के कबीलों ने रोमन सेना के खिलाफ एक होकर मुकाबला किया परंतु जब भारत पर कोई हमला हुआ, कोई एक अकेली जाति हमलावरों से लड़ती रही। जब अधिकांश लोग मूकदर्शक बनकर खड़े हो जाएं तो कोई भी मार्शल जाति हमलावरों के सामने हमेशा टिकी नहीं रह सकती, हमेशा कामयाब नहीं हो सकती। हम हारे क्योंकि हम बंटे हुए थे। आज भी यदि हम समुदायों के आधार पर बंटते हैं तो और अधिक कमजोर होंगे।

हम अतीत के महान शिक्षकों से सीख लेने से इंकार करते है। रोचक बात है कि हमारे 5 हजार साल के इतिहास में हमने केवल दो बादशाहों–अशोक और अकबर को ''महान'' का दर्जा दिया है। निश्चय ही अनेक महान राजा और रानियां हुई हैं। आखिर हम चालुक्य, पल्लव और चोल राजाओं का बखान कर सकते हैं।

परंतु हमने अशोक और अकबर को ही महान क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अपने जमाने में फिरकावाराना फूट की उसी समस्या का सामना किया था जो हम आज कर रहे हैं। अशोक के जमाने में देश हिन्दुओं और बुद्धवादियों में बंटा था। दोनों समुदाय आपस में भिड़े हुए थे । अकबर के शासनकाल में एक अल्पसंख्यक समुदाय एक विशाल बहुसंख्यक समुदाय पर राज करने की कोशिश कर रहा था। दोनों बादशाहों के सामने एक जैसी समस्या थीः अपने जनता को एकताबद्ध कैसे करें? दोनों ने मेलमिलाप की बात कही। अशोक ने ''धम्म'' , लोगों का एक–दूसरे के प्रति नैतिक कर्तव्य, की बात कही। अकबर ने ''गंगा–जमुनी तहजीब'', हिन्दू और मुस्लिम सभ्यतों के मेल–मिलाप, की बात कही।

मेल–मिलाप और आत्मसातकरण हमारी सभ्यता की खास निशानी है। पश्चिमी सभ्यता से भिन्न, हमने निर्मूलन पर कभी विश्वास नहीं किया। हमने मेल–मिलाप पर विश्वास किया, सभ्यताओं के टकराव पर नहीं। इस प्रकार हमने विभिन्न संस्कृतियों एवं समुदायों, धर्मो एवं दर्शनशास्त्रों को सहज में अपनाया मानो वह हमारे अपने हैं। यह पृथ्वी पर एक चिस्थायी सभ्यता के तौर पर हमारे अस्तित्व एवं प्रगति का बुनियादी सिद्धांत है।

जो इससे अन्यथा समझते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि ''हम एकताबद्ध रहते हैं तो खड़े रह सकते है, बंट जाते हैं तो गिर जाते हैं''। एक देश के तौर पर हमारे इतिहास ने इस बात को बार–बार साबित किया है। तो भी, त्रासद है कि हम इस सरल ऐतिहासिक तथ्य को समझने में असफल रहते हैं।

इतिहास वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इतिहास जैसा भी है आपके सामने है और इससे आपको सीख लेनी चाहिए। यदि इतिहास आपको कष्ट पहुंचाता है तो और भी अच्छा है। क्योंकि उससे यह संभावना कम हो जाती है कि आप उसको दोहराना चाहेंगे। इतिहास हटाने या मिटाने के लिए नहीं है। यह हम सबका है।

बिहार में जेल भरो आंदोलन को मिली शानदार सफलता

पटनाः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी जिला समाहरणालय पर जन सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन संपन्न हो गया। इस आंदोलन को अपार सफलता मिली। बहुत दिनों के बाद इस तरह के आंदोलन आयोजित किये गए। जिसमें करीब डेढ़ लाख लोगों की जनभागीदारी हुई। 20 जून को राज्य के सात जिलों मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, बांका, नवादा और शिवहर में भाजपा हटाओ देश बचाओ और नया भारत बनाओ नारे के साथ जन सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन आयोजित किये गए जबकि गया में 21 जून को कार्यक्रम आयोजित किये गए। इससे पहले आठ और नौ जून को बिहार के 29 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये गए थे।

कोरोना काल के बाद इस तरह की पहली कार्रवाई आयोजित की गई। इस आंदोलन से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आंदोलन की तैयारी को लेकर गांव गांव पदयात्रा निकाली गई। हजारों नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। मोटर साईकिल रैली निकाली गई। यह आंदोलन केंद्र की जन विरोधी भाजपा सरकार को हटाने के लिए आयोजित की गई।

भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ, नारे के साथ जन सत्यग्रह और जेल भरो आंदोलन चलाया गया है। सुबह साढ़े नौ बजे से समाहरणालय का गेट जाम कर दिया गया। दरभंगा में जिलाधिकारी कार्यालय का गेंट तोड़कर आंदोलनकारी अंदर प्रवेश कर गए। बेगूसराय में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर सदर थाने ले जाया गया। थाने में आंदोलनकारियों को रखने के लिए जगह नहीं थी। सहरसा में भी पुलिस आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। थाने में जगह नहीं थी। इसलिए आंदोलनकारियों को तुरंत रिहा कर दिया गया।

मधुबनी में आंदोलन का नेतृत्व राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय, जिला सचिव मिथिलेश कुमार झा, संजय चौधरी, राजश्री किरण, बेगूसराय में जिला सचिव अवधेश कुमार राय, राज्य सचिवमंडल सदस्य राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विधायक रामरतन सिंह, विधायक सूर्यकांत पासवान, दरभंगा में राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा, जिला सचिव नारायण जी झा, सहरसा में राज्य सचिव मंडलसदस्य ओमप्रकाश नारायण, जिला सचिव परमानन्द ठाकुर, पूर्व जिला सचिव विजय कुमार यादव, बांका में राज्य सचिव मंडल सदस्य व पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार, नवादा में प्रो. जयनंदन सिंह और शिवहर में राज्य सचिवमंडल सदस्य रामचंद्र महतो, राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार सिंह, जिला सचिव शत्रुघन साहनी, गया में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जानकी पासवान, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश कुमार जिला सचिव सीताराम शर्मा, मसूद मंजर आदि ने आंदोलन का नेतृत्व किया और गिरफ्तारी दी।

आंदोलन के दौरान वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी सरकार सभी मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को फासीवादी रास्ते पर ले जाना चाहती है। देश में साम्प्रदायिक जहर घोला जा रहा है। साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। इस सरकार में दलित, आदिवासी, महिलाओं और अल्पसंख्यक पर अत्याचार बढ़े हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कल कारखाने बंद हो रहे हैं।

भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, हमदर्द और राज्य की जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के 38 में से 37 जिलों में आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है जबकि सुपौल में 27 जून को कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि यह आंदोलन संविधान की रक्षा करने, महंगाई पर रोक लगाने, किसानों को समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, कृषि के कंपनीकरण की साजिश पर रोक लगाने, मनरेगा के बजट में की गई कटौती वापस लेने, अडानी–अम्बानी पक्ष में बनाई जा रही नीति पर रोक लगाने, सार्वजनिक उपक्रमों के सौदे को रद्द करने, मौलिक अधिकारों पर हमले बंद करने, केन्द्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को रद्द करने, समान शिक्षा की नीति लागू करने आदि मांगों को लेकर आयोजित किये गए। मोदी सरकार में लगातार संवैधानिक अधिकारों पर हमले किये जा रहे हैं। मोदी सरकार भाजपा आरएसएस के एजेंडे को देश पर थोपना चाहती है। इस सरकार में महंगाई आसमान छू रही है।

दिल्ली के ट्रेड यूनियनों के जारी विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, 04 जुलाई 2023: संयुक्त ट्रेड यूनियनों के दिल्ली मंच द्वारा संयुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, कर्मपुरा, नई दिल्ली (जिला पश्चिम) पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका संचालन एटक, दिल्ली राज्य कमेटी के उपमहासचिव मुकेश कश्यप ने किया।

दिल्ली इंटक के नेता तरसेम राज, दिल्ली एटक के महासचिव सतीश कुमार, उप महासचिव विजय कुमार तिवारी, एटक दिल्ली राज्य कमेटी के सचिव संजीव कुमार राणा, राजेश कश्यप उपाध्यक्ष व एटक राज्य कमिटी सदस्य बृजभूषण तिवारी, रामेश्वर भारतीय, संजय कुमार शुक्ला नेता ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन नेता, पवनसुत समस्त कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, एचएमएस दिल्ली की सचिव मनजीत अहलवलिया, सचिव नारायण सिंह, राजेंद्र कुमार, सीटू दिल्ली के उपाध्यक्ष प्रो. सिद्धेश्वर शुक्ला, प्यारेलाल तथा अन्य वरिष्ठ नेता सुरेन्द्र कुमार, उमेश कुमार, ओमप्रकाश तिवारी, संजीव कुमार तिवारी आदि ने सम्बोधित किया।

प्रदर्शनकारी नेताओं ने संयुक्त श्रमायुक्त श्री एस के गुप्ता को एक ज्ञापन दिया तथा माँग की कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित 4 लेबर कोड दिल्ली में अधिसूचित न करें तथा न्यूनतम वेतन दिल्ली में 26 हजार रुपये मासिक घोषित किया जाये तथा मौजूदा न्यूनतम वेतन की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक संस्थान में लागू कराया जाये तथा सभी श्रम कानूनों की अनुपालना श्रम विभाग कराये।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आग्रह किया कि इस ज्ञापन को दिल्ली सरकार को प्रेषित किया जाये तथा 9 अगस्त 2023 के संयुक्त केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के "महापड़ाव" से भी अवगत कराया।

पोन्नीलन के उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद 'ब्लैक सॉइल' का लोकार्पण

'भारत जोड़ो' का साहित्यिक समारोह

जगदीश चंद

तमिल भाषा के मशहूर लेखक, साहित्य अकादेमी से सम्मानित और प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पोन्नीलन के तमिल में लिखे उपन्यास 'करिसल' के अंग्रेजी अनुवाद 'ब्लैक सॉइल' का लोकार्पण और पुस्तक–चर्चा कार्यक्रम प्रलेस दिल्ली राज्य इकाई के तत्वाधान में 30 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित साहित्य अकादेमी के सभागृह में सम्पन्न हुआ। अंग्रेजी में अनूदित इस किताब का प्रकाशन पेंगविन इंडिया ने किया है।

"बुरी तरह बहते पसीने को वो अपनी धोती के सिरे से सूखा रहा था। जब जिंदगी के कोई आसार उसे कहीं नजर नहीं आए तो एक खौफनाक एहसास ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। बंजर और खनकड़ मिट्टी का ऐसा खुश्क इलाका उसने पहले कभी नहीं देखा था। चिंघाड़ती हुई धूल भरी अंधियां इस इलाके पर हमला–आवर रही थीं।

बरगद का एक विशाल वृक्ष छतरी की तरह थोड़ा सा ठंडा साया फराहम करता नजर आया। इसकी शाखों पर कौए और मेंनाएं फुदक रहे थे। हवा से पत्ते हिल रहे थे और हवा के झौंकें उसे थपकियां देकर आराम देने की दावत दे रहे थे। उसने सामने रास्ते पर निगाह डाली। दूर तक कोई दूसरा दरख्त नजर नहीं आया।

बाड़ की झाड़ियों पर चंद कपड़े सूख रहे थे जिनसे इन्सानी बस्ती का पता चलता था। किसी बूढ़े किसान के नंगे सीने जैसे शुष्क मिट्टी के इस नजारे से उसका दिल उदासी से भर गया।

. . . अचानक गर्द–ओ–गुबार का एक बड़ा सा बगूला उठा और चिमनी के मुँह की शक्ल में आगे बढ़ने लगा मिट्टी को चीरता हुआ, धूल भारी हवा को हर तरफ दायरों में गर्दिश देता हुआ– तेज हवा के एक और झौंके ने, जो पहले से ज्यादा गजबनाक होकर उठा था, विशालकाय बरगद को उखाड़ फेंकने की कोशिश की तो उसने कनप्पन का ध्यान अपनी तरह खींच लिया। नन्हे परिंदे जो बरगद में पनाह लिए हुए थे, डर के मारे उड़ने लगे। धूल भरी हवा ने जमीन के मंजर को पहाड़ी कोहरे की मानिंद अपनी चादर में लपेट लिया।...

... "वीराया मेरी बीवी, यानि तुम्हारी माईनी, तुम्हारे पास आएगी उसे कम से कम बर्तन भर बाजरा दे देना, बच्चे कल से भूखे हैं।"

अनूदित उपन्यास के पहले अध्याय के उपरोक्त शुरुराती अंश का पाठ अनुवादक जे. प्रियदर्शिनी ने अंग्रेजी में और उसका हिन्दी पाठ अर्जुमंद आरा, प्रगतिशील लेखक संघ की दिल्ली राज्य अध्यक्ष ने किया। उपरोक्त अंश तमिलनाडु के वर्षा आधारित क्षेत्र, तमीरबरनी नदी के नजदीक, करिसल गाँव में, एक स्कूली अध्यापक, कन्नपन की पोस्टिंग के इर्द–गिर्द घूमते उपन्यास के माध्यम से उस काली मिट्टी या काबर मिट्टी वाले सूखे, अभावग्रस्त, साधनहीन

क्षेत्र में इन्सानों की इन्सानों के साथ और इंसानों की प्रकृति के साथ गुत्थम–गुत्था से आमना–सामना कराते हैं।

इस पाठ से पहले उपन्यास लोकार्पण और इस पर चर्चा की शुरुआत के लिए प्रलेस दिल्ली राज्य सचिव अर्जुमंद आरा ने कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी प्रलेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत तिवारी को सौंपी। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिन्दी के वरिष्ठ लेखक, पत्रकार प्रलेस दिल्ली राज्य समिति के अध्यक्ष मण्डल सदस्य राम शरण जोशी ने की।

कार्यक्रम संचालन के दौरान विनीत तिवारी ने गैर–हिन्दी भाषी लेखक की कृति पर सभागृह में उपस्थित हिन्दी, उर्दू जगत के वरिष्ठ लेखकों की मौजूदगी पर अपनी खुशी जाहिर की। विनीत ने आगे कहा कि 1960–1970 के दौरान जमींदारी व्यवस्था और भूमि सुधार की मांग को लेकर देश भर में उठे आंदोलनों की अग्रणी जीवानन्द के संपर्क में आए, प्रलेस के साथ सक्रिय रहे। उपन्यास, लघु कहानी संग्रहों, संस्मरणों, रेखाचित्रों, आलोचनात्मक निबंधों और अनुवाद के लिए पोन्नीलन मशहूर हैं। उनके तमिल उपन्यास 'पुदिया दरिसानंगल' को 1994 में साहित्य अकादेमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस उपन्यास को 2016 में एस नागराजन ने 'न्यू दर्शनंस' के शीर्षक से अंग्रेजी में अनूदित किया जिसे साहित्य अकादेमी ने प्रकाशित किया है। 'ब्लैक सॉइल', उपन्यास मूल तमिल भाषा में करिसल (काली मिट्टी) के नाम से पहली बार 1976 में प्रकाशित हुआ था आज भी तमिल पाठकों के बीच चाव से पढ़ा जाता है। 'करिसल' का हिन्दी में एक अनुवाद मीनाक्षी पूरी ने किया है लेकिन वह अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है।

अनुवादक जे. प्रियदर्शिनी का परिचय देते हुए विनीत ने बताया कि वे पोन्नीलन की पोती हैं, पेशे से डाक्टर हैं। प्रियदर्शिनी का उपन्यास में खिंचाव इस तरह का रहा कि उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में जब इसे पढ़ना शुरू किया तो वे इसे बीच में न छोड़ सकी और तीन दिन में उन्होंने इसे पढ़ डाला। बचपन से इस किताब के प्रति लगाव ने उन्हें इस किताब के अंग्रेजी अनुवाद के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस उपन्यास का अनुवाद फोन पर घर से अस्पताल के लिए काम पर जाते हुए या अस्पताल में थोड़ा भी खाली समय मिलने के दौरान यहाँ तक कि अपने प्रसवकाल में शिशु जन्म की प्रतीक्षा में पूरा किया।

उपन्यास के लोकार्पण से पूर्व विभूति नारायण राय, अर्जुमंद आरा और रामशरण जोशी ने पोन्नीलन और प्रियदर्शिनी को स्वागत सम्मान के रूप में शाल ओढ़ाया। इसके बाद हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी ने पोन्नीलन के अंग्रेजी में अनूदित उपन्यास ब्लैक सॉइल का लोकार्पण किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में तमिल साहित्य की प्रोफेसर डी उमा देवी, अर्जुमंद आरा, विभूति नारायण राय, जे. प्रियदर्शिनी पुस्तक–चर्चा में शामिल वक्ता थे।

उपन्यास पर अपने विचार रखते हुए विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा कि अनूदित किताब का इतना सरल अनुवाद किया गया है कि यदि यह किताब अब से बीस बरस पहले मिली होती तो इस किताब को मूल में पढ़ने के लिए मैं तमिल सीखता लेकिन अभी में तिरानबे साल में हूँ अब इस अनूदित कृति से ही संतुष्ट हूँ। सरल अनुवाद करना सीधी लाइन खींचने जैसा टेढ़ा काम है। अभी के राजनीतिक माहौल में यह किताब 'भारत जोड़ो' के साहित्यिक समारोह के जैसे है, उहोने प्रलेस को इस काम के लिए बधाई दी और गैर–हिन्दी भाषी राज्यों से अन्य रचनाकारों और उनकी कृतियों पर आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि ब्लैक सॉइल उपन्यास के संदर्भ में प्रेमचंद के साहित्य का दिक–काल याद करें तो हम पाएंगे उनकी रचनाओं का स्थान कानपुर से पूर्व और पूर्व से पश्चिम का रहा है और रचनाकाल औपनिवेशिक भारत का 1930 के आसपास का दशक रहा है, प्रेमचंद की रचनाओं में हमें समस्याओं से घिरे आदमियों–औरतों की जिंदगियों की कहानियाँ मिलती हैं। पोन्नीलन की किताब ब्लैक सॉइल में तमिल नाडु के दक्षिणी हिस्से के तूतुकुड़ी जिले के नगलपुरम का काली मिट्टी वाला बारिस पर आश्रित क्षेत्र है जहाँ बरसात में नदी, पोखर में भरा पानी गर्मी में सूख जाता है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने किताब की विशेषताओ पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि किताब में जमीन, प्रकृति और मौसम की विविधताओं के कई वर्णन हैं। उपन्यास में इंसानों के इतर कई अन्य छोटे पात्र हैं जैसे कुत्ते, गिलहरी, बकरी आदि। उपन्यास की घटनाओं, पशु, पक्षियों और मनुष्यों के बीच अंतर सामंजस्य है। उपन्यास में आंदोलन का वर्णन ऐसे है जैसे जमीन से अनाज पैदा होता है, वैसे ही फसल पैदा हो रही है, आंदोलन पैदा हो रहा है, आंदोलन के नेता पैदा हो रहे हैं, लेखक पैदा हो रहा। उपन्यासकार मामूली आदमी की जिंदगियों को, उनके अभावग्रस्त जीवन को, इस जीवन के खिलाफ संघर्ष को करुणा के माध्यम से उसके उदात्त स्वरूप तक ले जाता है। उन्होंने कहा कि अध्यापक के चरित्र में उपन्यास के पात्र कन्नपन में उपन्यासकार पोन्नीलन के व्यक्तित्व का आभास मिलता है। उपन्यास एक महिला किरदार पुन्नी के प्रति कन्नपन के आकर्षण को साधन उन्मुक्त प्रेम के रूप में बयान करते हुए त्रिपाठी जी उस प्रसंग का जिक्र करते हैं जब कन्नपन पुन्नी से पूछता है कि क्या तुम्हारा संबंध पहले भी किसी के साथ रहा है, यहाँ पुन्नी नहीं कह सकती थी, लेकिन वहाँ एक संक्षित बयान मिलता है कि पहले था अब नहीं है। उन्होंने कहा कि उपन्यास में वर्णित संघर्षो के बीच पोन्नीलन संवेदनशीलता के साथ अगाध मानवीय संबंध के रूप में पुन्नी और कन्नपन के बीच प्रेम के उदात्त स्वरूप को चित्रित करते हैं।

इसी संदर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि किसी व्यक्ति का करुणा के रूप में स्वत्व,'मैं' तभी बनता है जब वह उदात्त स्वरूप लेता है। अपनी बात का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि "इस किताब के हिन्दी में अनुवाद की आशा करता हूँ। इस कार्यक्रम से मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। प्रलेस के इस काम से मुझे खुशी हो रही है"।

उपन्यास चर्चा में शामिल अगली वक्ता डी उमा देवी ने कहा कि यह उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। पौन्नीलन व्यक्तित्व विकास में 'अरेइची' पत्रिका का सहयोग रहा है। ब्लैक सॉइल जिसे तमिल में 'करितल' कहा जाता है की स्थानिक भूगोलिक

शेष पेज 15 पर...

प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी उज्ज्वला योजना की हकीकत

प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना की हकीकत तब सबसे ज्यादा उजागर होकर सामने आयी जब यह सच सामने आया कि इस योजना के पोस्टर में जिन महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देते हुए दिखाया गया है, वो भी चूल्हे पर खाना बना रही है। उप्र की गुड्डी जिसे पीएम मोदी को गैस सिलेंडर देते हुए दिखलाया गया था वहीं चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर है। इस पर बीबीसी ने उस महिला से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास गैस भरवाने के पैसे नहीं हैं। ये तो थी पोस्टर वाली महिला की बात। सरकारी आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि करीब 20 फीसदी लोग दोबारा गैस भरवाने जा ही नहीं रहे हैं।

इस स्कीम की दूसरी पोस्टर वुमेन हैं मऊ की रहने वाली जरीना। प्रधानमंत्री ने बलिया में जरीना को भी गैस कनेक्शन दिया था। जरीना के घर में सिलेंडर है लेकिन जब हम उनके घर पहुंचे तो वो मिट्टी का चूल्हा बना रही थीं। जरीना की मजबूरी गुड्डी जैसी ही है। जरीना ने 3 साल में केवल 14 सिलेंडर भरवाए हैं।

मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना 'मुफ्त' नहीं?

उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने एक कनेक्शन की कीमत 3,200 रुपए निर्धारित की है। इसमें से 1600 रुपए तो सरकार वहन करेगी, जिसमें सिलेंडर का सिक्योरिटी डिपोजिट, ईस्टालेशन, पाइप, रेगुलेटर आदि शामिल है। इसके अलावा बाकी के 1600 रुपए ग्राहक को देने होंगे, जिसमें दो बर्नर वाले चूल्हे की कीमत और पहली रिफिल की कीमत शामिल है।

उज्ज्वला योजना बेशक सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जिससे गरीब तबके के लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार अपनी इस कोशिश में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत से लोग गैस सिलेंडर भरवाने दोबारा जाते ही नहीं। खुद गुड्डी ही कहती हैं कि महंगा होने के चलते वह तीन साल में महज 11 सिलेंडर ही भरवा पाई हैं, जबकि सरकार की ओर से हर साल 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाते हैं। मोदी सरकार ने इस स्कीम को काफी जल्दबाजी में शुरू किया। जिसे इस योजना के लागू करने की स्टडी करने को कहा गया था, उसने उसके नतीजों का इंतजार भी नहीं किया। उज्ज्वला योजना पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाने की ये एक बड़ी वजह है। लेकिन बावजूद इसके, जो लोग अब तक गैस कनेक्शन से वंचित थे, कम से कम उनमें से 80 फीसदी का मुख्यधारा में आ जाना भी काफी अच्छा है।

यानी 1600 रुपए तो आपको देने ही होंगे, तभी गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि, सरकार ने इससे राहत दिलाने का एक शानदार तरीका भी निकाला है, जिसमें आप 1600 रुपए की रकम को ईएमआई में बदलवा सकते हैं। ये 1600 रुपए आपको मिलने वाली सब्सिडी से एडजस्ट होंगे। यानी जब तक लोन की रकम 1600 रुपए पूरी रिकवर नहीं हो जाती है, तब तक ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिलेगी और फिर उसके बाद सब्सिडी सीधे उनके खातों में जाना शुरू हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि इय योजना में मुफ्त जैसा कुछ भी नहीं है।

भारत में भी तकरीबन 50 करोड़ लोग आज भी पारंपरिक चूल्हों पर खाना बनाते हैं। जो शहरी लोग गैस पर खाना पकाकर खाने के आदि हैं उनके लिए तो चूल्हे पर पके खाने का स्वाद हमेशा ही पहली पसंद होती है, कईयों ने तो ग्रामीण टूरिज्म में चूल्हे पर पके खाने का व्यंजन अपने मेनू कार्ड में डाल दिया है। पर जो फेफड़े इन चूल्हों की आग जलाए हुए हैं उनका क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल तकरीबन 15 लाख लोगों का अंदेशा जताया था। घरेलू प्रदूषण और मौत के आंकड़े को देखते हुए केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के रूप में सामने आई। परंतु इस योजना में ना कुछ मुफ्त है और ना ही गैस का उपयोग जारी रखने के लिए कुछ है।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने रसोई गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इस योजना की शुरूआत की। जिसके तहत बीपीएल परिवार की महिला, जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है वह निःशुल्क गैस सिलेंडर पाने की हकदार बनी। इस योजना की जानकारी आपको सभी पेट्रोल पंप पर प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के फोटो के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स में दिख जाएगी। सरकार ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बांटकर अपनी पीठ थपथपाने को बेचैन दिख रही है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जिन महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं, क्या वे दोबारा सिलेंडर में गैस भरवा पायी या नहीं?

इस योजना का लाभ पाने के लिए आज भी कई गरीब परिवार काम/धंधा किनारे धरकर एजेंसी के बाहर लाइन लगाए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जिन्हें सूची में जगह मिल गई है उनके नाम पर धोखाधड़ी हो रही है कोरोना काल में और ताला बंदी की वजह से जहाँ गरीबों ने अपनी आजीविका का साधन गंवाया, वही प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम पर पहले 3 महीने यानी अप्रैल, मई और जून के लिए केंद्र सरकार की और से सभी उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रहे परिवारों के खाते में गैस की रकम डालने का एलान हुआ और ऐसा माना गया की सभी उज्ज्वला धारकों ने तो अपना बैंक अकाउंट यानी जनधन खाते पहले से ही दे रखा है इसलिए उनके खाते में आसानी से गैस की रकम पहुंचा दी जाएगी और इस पैसे का इस्तेमाल केवल गैस खरीदने के लिए ही परिवार इस्तेमाल करेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

किसी जंग से कम नहीं था सिलेंडर पाना

बिहार के जमुई जिले के मिर्चा गांव से मुन्ना पाठक बताते हैं कि कुछ साल पहले मां के नाम से उज्जवला योजना के लिए पंजीयन करवाया था। मुन्ना कहते हैं सारे जरूरी दस्तावेज जमा करवाए थे पर सिलेंडर नहीं मिला। अब मां भी गुजर गई, परिवार में कोई और महिला नहीं है। इसलिए सिलेंडर मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई। पहले मां चूल्हा फूंक रही थी अब मैं फूंक रहा हूं। गाजीपुर के जलालाबाद के विशुनपुरा निवासी सत्यदेव राजभर कहते हैं कि योजना का लाभ पाने के लिए बहुत मुश्किल से सारे कागज जमा किए थे। बहुत कोशिशों के बाद पात्रता सूची में नाम आया पर सिलेंडर आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इसका जवाब ना तो एजेंसी वाले देते हैं ना कही और से कुछ पता चलता है। सत्यदेव कहते हैं कि अगर योजनाएं ऐसी ही हैं तो फिर उन्हें बनाने की जरूरत ही क्या है? गरीब आदमी तो चूल्हा ही फूंक रहा है।

राष्ट्रीय सांख्ययिकी कार्यालय की साल 2018 की रिपोर्ट की मानें तो इस योजना के लाभार्थियों तक सुविधा पहुंची ही नहीं है। सरकार ने 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को एक साथ निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे थे। लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि करीब 43 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं ऐसी रहीं जो केवल एक बार गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकीं और फिर चूल्हे पर लौट आई। डाटा बताता है कि पिछले 4 सालों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन ने ग्रामीण भारत में कुल एलपीजी कनेक्शन में 71 फीसदी की बढोत्तरी की है। हालांकि यह हकीकत सरकारी कागजों पर दर्ज हुई है। एनएसओ के सर्वे में बताया गया है कि योजना के 43 प्रतिशत लाभार्थी चूल्हे पर ही खाना बना रहे हैं।

जमुई के चकाई प्रखंड के रहने वाले परमेश्वर कहते हैं कि मेरा नाम योजना की पात्रता सूची में है पर सिलेंडर नहीं मिला। जब पता करने गए तो एजेंसी वालों ने कहा कि मेरे नाम का सिलेंडर किसी और को दे दिया गया है। जब पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ना तो हमारी शिकायत कोई दर्ज करता है ना ही मदद. सरकार को लग रहा होगा कि गरीबों को सिलेंडर मिल रहा है पर हकीकत में तो ऐसा नहीं है।

बिचौलियों का खेल भी है जारी

गाजीपुर जनपद के जखनियां ब्लॉक के रायपुर की मीरा बताती हैं कि दो साल पहले एक बिचौलिए को सारे कागज और फार्म भरकर दिए थे। वो बोला था कि कनेक्शन दिलवा देगा पर ऐसा हुआ नहीं। एजेंसी में पता किया तो बोलते हैं कि कनेक्शन तो मिल चुका है और सिलेंडर भी जा रहा है पर कहां जा रहा है पता नहीं? क्योंकि हमें तो आज तक नहीं मिला। रायपुर में मीरा जैसी और भी कई महिलाएं हैं जो इन्हीं बिचौलियों के चक्कर में योजना से वंचित रह गई।

गांव की ही अंजना कहती हैं कि हम तो पढ़े/लिखे हैं नहीं, गांव का ही एक आदमी हमसे बोला था कि फ्री में गैस सिलेंडर दिलवाएगा। हमने उसके सब कागज दे दिए थे पर सिलेंडर नहीं मिला। अब तो दो साल हो गए। जिससे काम करवाया था वो आदमी भी मर गया। एजेंसी वाले कहते हैं उसी को साथ लाओ जिसने कनेक्शन दिलवाने का कहा था। अब कहां से लाएं उसे?

ज्यादातर गांवों में यही स्थिति है। गांव की महिलाएं योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखती थीं। फार्म भरना उनके बस में नहीं था जिसका फायदा एजेंसी संचालकों और बिचौलियों ने खूब उठाया। एजेंसी के चक्कर लगाना, बिचौलियों से बहस करना गरीब परिवारों के बस की बात नहीं। इसपर से कंडे और लकड़ी सुलभता से मिल भी जाते हैं इसलिए लोग वापिस पारंपरिक चूल्हों का रूख करने लगे है।

झारखंड के पेटरवार के गो पंचायत में गैस एजेंसी संचालक गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं जिसके कारण उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। एजेंसी जाने पर उन्हें बताया जाता है कि सिलेंडर पहले ही भिजवाया जा चुका है। कुलगो डुमरी गैस एजेंसी की तरफ से उज्ज्वला योजना के करीब 200 लाभार्थियों को सिलेंडर दिया जाना है पर ये सिर्फ कागजों पर चल रहा है। गैस सिलेंडर एक बार देने के बाद एजेंसी वाले महीनों तक शक्ल नहीं दिखाते, सिलेंडर रिफिल नहीं होते और मजबूर होकर घरों में फिर से चूल्हा जलने लगता है। जबकि सरकारी दस्तावेजों में इन परिवारों को समय पर गैस आपूर्ति हो रही है। इसी तरह झारखंड के हजारीबाग के टाटीझरिया से भी ग्रामीण यही शिकायत कर रहे हैं। गैस एजेंसी का नाम भी कुलगो गैस एजेंसी बताया जा रहा है। गांव की जासो देवी, जेमनी देवी, ललिता देवी, हेमंती देवी समेत दर्जनों परिवारों की महिलाएं एजेंसी के चक्कर काट–काटकर परेशान हैं।

कोरोना काल टूट गई कमर

इस योजना का दम पहले से ही घुट रहा था पर कोरोना काल में इसी हालत बद से बदत्तर हो गई थी। जिन कुछ लाभार्थियों को उम्मीद थी कि खाते में सिलेंडर की राशि पहुंच जाएगी वे अब तक इंतजार ही कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने मार्च के आखिरी सप्ताह में 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। जिसमें लॉकडाउन के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से गरीब लोगों को उबारने के उद्देश्य से किया गया था। इसके तहत अप्रैल से जून तक उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने की भी घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत लगभग 7.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 9,670 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। लेकिन 76.47 लाख महिलाओं के खाते में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की जा सकी। अब सरकार कह रही है कि इनमें से 31 लाख महिलाओं को खाते में समस्या के कारण सरकारी मदद नहीं मिल सकी। पर सवाल ये है कि खाते की दिक्कत कोरोना काल में ही सामने कैसे आई? क्योंकि इसके पहले उनके खातों में सब्सिडी की राशि पहुंचाई गई थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 31 लाख लाभार्थी खाते में धनराशि स्थानांतरित नहीं कर सके, क्योंकि खाता आधार से लिंक नहीं था, या केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण खाता बंद या निष्क्रिय था।

जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से 72.96 लाख (अप्रैल से जून) के खाते में भेजी गई राशि लाभार्थियों को मिली है। इसके अलावा, इंडियन ऑयल की ओर से 2,58,746 लेनदेन (1 अप्रैल से 29 जुलाई) विफल रहे हैं. जबकि भारत पेट्रोलियम के 92,331 लेनदेन (1 अप्रैल से 8 अगस्त) विफल रहे हैं।

छात्रों एवं शिक्षकों के खिलाफ गैर–जनतांत्रिक कार्रवाई

दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय की प्रशासनिक निरंकुशता की निन्दा

पटना: केदार दास श्रम एवं समाज अध्ययन संस्थान ने दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में प्रशासन की निरंकुशता और छात्रों एवं शिक्षकों के खिलाफ गैर–जनतांत्रिक कार्रवाई की तीव्र भर्त्सना करता है। केंद्र की वर्तमान सरकार दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के स्वायत्त चरित्र में लगातार दखलंदाजी कर छात्रों और शिक्षकों के जनतांत्रिक एवं कानून प्रदत्त अधिकारों पर हमला कर रही है। पिछले वर्ष दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने देय वृत्ति में की गई कटौती के खिलाफ जब विरोध जताया, तब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको विश्वविद्यालय से निष्कासित करने जैसी असंवेदनशील कार्रवाई की गई। छात्रों पर की जा रही निरंकुश कार्रवाई के खिलाफ दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के कुछ संवेदनशील शिक्षकों ने जब आवाज उठाई और पूरे मामले को छात्र समुदाय एवं विश्वविद्यालय के व्यापक उद्देश्यों के हित में सुलझाने की अपील की, तब बजाय उनकी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिसंबर, 2022 में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एक जांच समिति का भी गठन किया गया जिसने 19 मई 2023 को विश्वविद्यालय के चार शिक्षकों को बहुत ही अपमानजनक तरीके से एक लंबी प्रश्नावली सौंपी और समिति के सामने ही हस्तलिखित अपना उत्तर देने को कहा। आरोपित शिक्षकों ने जब अपना उत्तर देने के लिए समय की मांग की, तो उसे देने से इंकार कर दिया गया और 16 जून 2023 को चार शिक्षकों–अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. स्नेहाशीष भट्टाचार्य, कानूनी अध्ययन विभाग के डॉ. श्रीनिवास बुरा, सामाजिक विज्ञान विभाग के डॉ. इरफानुल्लाह फारूकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के डॉ. रवि कुमार–को निलंबित कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनसे अपना परिचय पत्र, प्रशासन द्वारा दिया गया लैपटॉप आदि लौटा देने का निर्देश दिया है और दिल्ली से बाहर न जाने का निर्देश देते हुए प्रति कार्य दिवस को हाजिरी लगाने को कहा है।

दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय प्रशासन के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ उठाए गए कदम न सिर्फ निरंकुश और गैर–जनतांत्रिक चरित्र के हैं, बल्कि विश्वविद्यालय के घोषित मूल्यों और उद्देश्यों के भी विपरीत हैं। केदार दास श्रम एवं समाज अध्ययन संस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन और भारत सरकार से अपील करता है कि वे तत्काल छात्रों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढें, निष्कासित छात्रों का निष्कासन वापस लें और निलंबित शिक्षकों का निलंबन तत्काल वापस लें।

अहमदाबाद में सद्भावना दिवस मनाया गया

अहमदाबाद: सांप्रदायिक सद्भावना के लिए शहीद हुए राजबली लखाणी और वसंत राव हेंगिश्टे के याद में अहमदाबाद में हर वर्ष की पहली जुलाई को वामपंथी पार्टी और नागरिकों द्वारा सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 1946 में देश में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे अहमदाबाद भी इससे अलग नहीं था।

पहली जुलाई के दिन शांति स्थापित करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस भवन में लोग एकत्र हुए थे जिनमें कम्युनिस्ट, कांग्रेस के लोग प्रमुख थे। उसी समय शहर के जमालपुर एरिया से सूचना मिली कि खाड़ की शेरी में दंगे भड़क उठे हैं और एक समुदाय दूसरे समुदाय पर हमला करने की तैयारी में है। इस घटना से उपस्थित व्यक्तियों में सन्नाटा छा गया, लेकिन एक आवाज आयी, मैं खाण शेरी जा रहा हूँ, यह आवाज राजबली लखाणी की थी। वह कम्युनिस्ट पार्टी में काम करने के साथ साथ कांग्रेस सेवादल में भी सक्रिय थे। उनकी आवाज के साथ दूसरी एक आवाज और भी आयी। मैं भी साथ चल रहा हूँ, यह दूसरी आवाज वसंत राव हेंगिश्टे की थी। लोगों ने उन्हें वहां न जाने के लिए बहुत समझाया लेकिन उन दोनों कहा कि शांति स्थापित करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं तो फिर हमें वहां जाना चाहिए इसलिए हम वहां जा रहे हैं। और वह दोनों वहां पहुचकर दोनों समुदायों को समझाने का प्रयास किया लेकिन लोग तो साम्प्रदायिकता के जहर से पागल हो रहे थे। उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि पहले तुम्हे हमको मारना होगा उसके बाद इन्हें मर सकते हो, सांप्रदायिक भीड़ ने दोनों को मर दिया फिर उसके बाद तो वही हुआ जिसका डर था।

आज पहली जुलाई को जमालपुर स्थित वसंत रजब स्मारक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गुजरात राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और अहमदाबाद के पार्टी प्रभारी रामसागर सिंह परिहार, जिला सचिव रमेश परमार, सहायक जिलासचिव दिनेश चौहान एवं नटवर देसाई और बडी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में प्रबुद्ध कर्मशील और पत्रकार प्रकाश एन शाह और सेक्युलर डेमोक्रेसी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

वाम दल हरियाणा में शुरू करेंगे संयुक्त अभियान

पानीपत, 4 जुलाई 2023: भाकपा के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 3 जुलाई को जसबीर स्मारक, रोहतक में भाकपा व माकपा की एक राज्य स्तरीय बैठक भाकपा के वरिष्ठ नेता रूप सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भाकपा के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप, सह सचिव तिलक राज विनायक, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रुप सिंह, भाकपा (मा) के राज्य सचिव सुरेन्द्र सिंह, राज्य सचिवमंडल सदस्य इन्द्रजीत सिंह, वीरेन्द्र मलिक ने भाग लिया।

भाकपा के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने मीटिंग में लिये गए फैसलों की जानकारी देते हुए आज यहां जारी एक प्रेस के नाम बयान में जारी करते हुए कहा कि वामपंथी नेताओं ने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा करते हुए नोट किया कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें अपने कुछ निकटतम पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां लागू कर रही हैं तथा लोगों की रोजी–रोटी, सामाजिक सद्भाव, संवैधानिक व जनतांत्रिक, नागरिक अधिकारों पर हमले कर रही हैं। इन सरकारों की विभाजनकारी राजनीति की बदौलत आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा हो गई है जिसका ताजा उदाहरण मणिपुर की हिंसा है।

दरियाव सिंह कश्यप ने कहा कि राज्य में भयंकर बेरोजगारी है, किसानों की फसलों के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है तथा फसल खराबी के मुआवजों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा, मनरेगा व कानून व्यवस्था चौपट हैं और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।

ऐसे हालात में भाजपा की कॉरपोरेट परस्त और विभाजनकारी राजनीति को शिकस्त देने और वैकल्पिक राजनीतिक मुद्दों को उभारते हुए दोनों वामपंथी पार्टियां प्रदेश में जन अभियान चलाएंगी। इसकी शुरूआत अगस्त महीने के अंत में जींद में राज्य स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन करके की जाएगी। यह जन लामबंदी और अभियान आगामी चुनावों तक जारी रहेगा और चुनावों में दोनों पार्टियां मिलकर उम्मीदवार उतारेंगी।

हरिशंकर परसाई: समाज की रग–रग से वाकिफ व्यंग्यकार

अदिति भारद्वाज

हरिशंकर परसाई व्यंग्य के विषय में खुद कहा करते थे कि व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। उनकी रचनाएं उनके इस कथ्य की गवाह हैं।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिन्दी साहित्य में व्यंग्य विधा के लिए, हर वर्ग के पाठक की चेतना में अगर किसी का नाम पहले–पहल आता है, तो वो परसाई ही हैं। व्यंग्य विधा को अपने सुदृढ़ और आधुनिक रूप में खड़ा करने में परसाई के योगदान को आलोचकों ने एक सिरे से स्वीकार किया है।

एक आधुनिक विधा के रूप में व्यंग्य की ख्याति 20वीं सदी में हुई। पाश्चात्य चिंतक जॉनथन स्विफ्ट व्यंग्य के विषय में कहते थे कि 'व्यंग्य एक ऐसा दर्पण है जिसमें देखने वाले को अपने अतिरिक्त सभी का चेहरा दिखता है।'

इस विधा का मुख्य उद्देश्य है, व्यक्ति और उसके सामाजिक संदर्भो में दिखने वाली किसी भी विसंगति पर कुठाराघात करना, भले ही यह संदर्भ, व्यक्ति और समाज के संबंध का हो सकता है, वर्ग और जाति के समीकरण का हो सकता है या विभिन्न विचारधाराओं के टकराव का। एक व्यंग्यकार, व्यक्ति–जीवन की विडंबनाओं का एक ऐसा रेखाचित्र खींचता है जिसे पढ़कर एक चेतन पाठक अपने आप से भी सवाल उठाने पर विवश हो जाता है।

व्यंग्य के विषय में स्वयं परसाई कहा करते थे 'व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है।'

22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के जमानी ग्राम में जन्मे परसाई मध्यवर्गीय परिवार से आते थे। अल्पायु में ही मां की मृत्यु के बाद पिता की भी कालांतर में एक असाध्य बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। अब चार छोटे भाई–बहनों की जिम्मेदारी परसाई पर ही थी। इस प्रकार इनका आरंभिक जीवन गहन आर्थिक अभावों के बीच बीता। अपने आत्मकथ्य 'गर्दिश के दिन' में उन्होंने बचपन की सबसे तीखी याद 'प्लेग' की भयावहता का जिक्र किया है। यह 1936 या 37 का समय होगा। मैं शायद आठवीं का छात्र था। कस्बे में प्लेग पड़ी थी। रात को मरणासन्न मां के सामने हम लोग आरती गाते। गाते–गाते पिताजी सिसकने लगते, मां बिलखकर हम बच्चों को हृदय से चिपटा लेती और हम भी रोने लगते। ऐसे भयकारी त्रासदायक वातावरण में एक रात तीसरे पहर मां की मृत्यु हो गई। पांच भाई–बहनों में मृत्यु का अर्थ मैं ही समझता था।

पर जिस गर्दिश की बात परसाई कहते थे, वह जीवन पर्यंत बनी ही रही। वे स्वयं स्वीकार करते थे कि गर्दिश का सिलसिला बदस्तूर है, मैं निहायत बेचैन मन का संवेदनशील आदमी हूं। मुझे चैन कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए गर्दिश नियति है। अपनी जीवनी में परसाई इस बात का खुलासा करते हुए कहते हैं कि बाल्यकाल में जिस व्यक्ति ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थीं उनकी बुआ। परसाई जी ने उनसे ही अपनी जिंदगी के कुछ मूल–मंत्र सीखे थे: जैसे, निस्संकोच किसी से भी उधार मांग लेना या बेफिक्र रहना। बड़े–से–बड़े संकट में भी वो यही कहते कोई घबराने की बात नहीं, सब हो जाएगा। संघर्षो से भरे अपने जीवन में परसाई ने स्वयं को सदैव मजबूत बनाए रखा: 'मैंने तय किया– परसाई, डरो किसी से मत। डरे कि मरे। सीने को ऊपर कड़ा कर लो, भीतर तुम जो भी हो। जिम्मेदारी को गैर जिम्मेदारी के साथ निभाओ।

परसाई के व्यक्तित्व में धार्मिक रूढ़िवादिता, जातीयता, धार्मिक कट्टरता इन सबके विरुद्ध जो एक खास किस्म का विरोधी तेवर दिखलाई पड़ता है उसका बहुत कुछ श्रेय वह अपनी बुआ को देते हैं। उनसे ही उन्होंने सीखा कि जातीयता और धर्म बेकार के ढकोसले हैं। स्वयं उनकी बुआ ने पचास साल की अवस्था में तमाम विरोधों के बावजूद एक अनाथ मुस्लिम लड़के को अपने यहां शरण दे रखी थी। जीविकोपार्जन के संदर्भ में भी परसाई ने कभी किसी बंधी–बंधाई परंपरा का निर्वाह नहीं किया। अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व और आदर्शवादी स्वभाव ने उन्हें किसी भी नौकरी में टिकने नहीं दिया। मैट्रिक की परीक्षा उतीर्ण करते ही उन्होने जंगल विभाग में नौकरी शुरू की। जंगल में ही सरकारी टपरे पर रहते थे। ईंटों की चौकी बनाकर, पटिये और चादर बिछाकर सोया करते थे, जहां चूहों की धमाचौकड़ी रात भर चलती थी। परसाई अपने इन दिनों के विषय में कहते हैं: 'चूहों ने बड़ा उपकार किया। ऐसी आदत डाली कि आगे की जिंदगी में भी तरह–तरह के चूहे मेरे नीचे उधम करते रहे हैं, सांप तक सर्राते रहे हैं, मगर मैं पटिये बिछाकर, पटिये पर सोता हूं।'

आर्थिक संकटों के बीच ही उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिन्दी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और छिट–पुट अध्यापन का कार्य शुरू किया। कुछ वर्षो तक अध्यापन कार्य करने के बाद उन्होंने 1947 में विद्यालय की नौकरी छोड़ दी। कुछ सालों बाद शाजापुर में एक कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त होने का प्रस्ताव आया, पर उन्होंने इसे भी अस्वीकार कर दिया और जबलपुर में रहकर स्वतंत्र रूप से लेखन करना स्वीकार किया। यहीं रहकर उन्होंने साहित्यिक पत्रिका 'वसुधा' का प्रकाशन और संपादन किया। इसके अतिरिक्त दैनिक अखबार 'देशबंधु' में 'पूछो परसाई से' स्तंभ भी बराबर लिखा जहां पर पाठकों के सवालों के माध्यम से विचार–विमर्श किया जाता रहा।

परसाई हिन्दी की प्रायः सभी प्रमुख पत्रिकाओं से स्तंभ लेखक के रूप में आजीवन जुड़े रहे। अपने पहले चरण में तो वसुधा दो वर्ष तक, लगातार प्रकाशित होती रही, जिसके संपादक

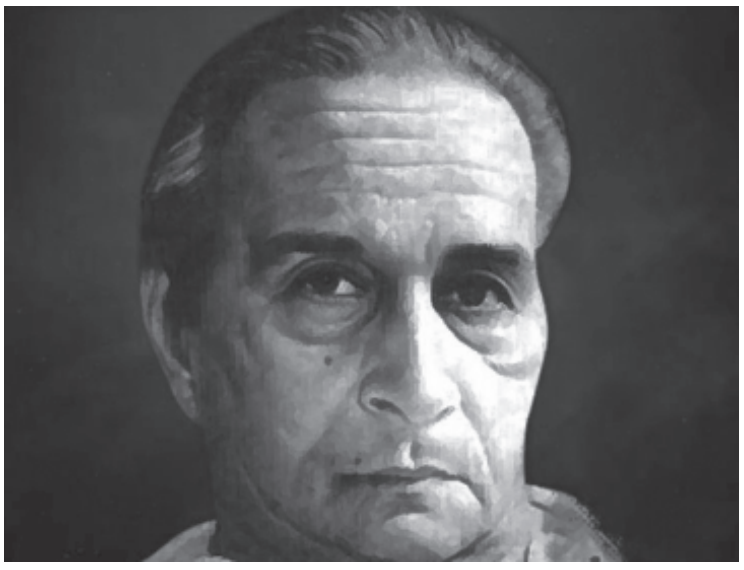

की भूमिका परसाई ने निभाई। हालांकि आर्थिक तंगी और संसाधनों के अभाव की वजह से दो वर्षो के बाद पत्रिका को बंद करना पड़ा। आगे चलकर मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ की पत्रिका के रूप वसुधा को एक बार फिर पुनर्जीवित किया गया और संघ के अध्यक्ष होने के नाते पत्रिका के संपादन का कार्यभार भी परसाई को ही दिया गया। 'मेरे समकालीन' शीर्षक से परसाई ने भी अपने स्तंभ की शुरुआत की थी। हालांकि इस प्रकार के स्वतंत्र लेखन की एक सबसे बड़ी अनिश्चितता यह रही कि आय की अनियमितता के कारण परसाई सदैव आर्थिक संकट में उलझे रहे। मसलन, अगर अखबार की आमदनी घट जाती या किसी अखबार में लंबी हड़ताल हो गई तो उनकी रचनाओं का मेहनताना भी उन्हें समय पर नहीं मिलता था।

और ऐसे समय में मित्रों और परिचितों से उधार मांगने के दौर चला करते थे, पर चेहरे पर शिकन नहीं आती और जीने का जज्बा बरकरार रहता। परसाई एक सफल व्यंग्यकार हुए, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह संभवतः यह भी है कि वह स्वयं पर भी व्यंग्य करने या अपनी खुद की आलोचना करने से नहीं डरते थे। अपनी जीवनी में उन्होंने बीसियों बार स्वयं के ऊपर एक तटस्थ आलोचक की तरह आत्मलोचन किया है। उनकी मर्मभेदी लेखनी ने अपनी कमियों को भी बारंबार उभारा है। मिसाल के तौर पर, परसाई अपने बेटिकट यात्रा करने के संदर्भ में कहते हैं: 'एक विद्या मुझे और आ गई थी– बिना टिकट सफर करना। जबलपुर से इटारसी, टिमरनी, खंडवा, इंदौर, देवास बार–बार चक्कर लगाने पड़ते। पैसे थे नहीं। मैं बिना टिकट बेखटके गाड़ी में बैठ जाता। तरकीबें बचने की बहुत आ गई थीं। पकड़ा जाता तो अच्छी अंग्रेजी में अपनी मुसीबत का बखान करता। अंग्रेजी के माध्यम से मुसीबत बाबुओं को प्रभावित कर देती और वे कहते–लेट्स हेल्प दि पुअर बॉय।'

वे एक जगह लिखते हैं:

'गैर जिम्मेदारी इतनी कि बहन की शादी करने जा रहा हूं। रेल में जेब कट गई, मगर अगले स्टेशन पर पूरी–साग खाकर मजे में बैठा हूं कि चिंता नहीं। कुछ हो ही जाएगा। और हो गया।' परसाई ने स्वयं अविवाहित रहते हुए अपने सभी भाई–बहनों की जिम्मेदारी का निर्वाह किया, पर उनके स्वयं का जीवन भी यातना–गर्भित व्यंग्य है।

काम के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें इस विषम जिंदगी को झेल जाने की वह शक्ति दी थी कि जीवन के प्रति एक वीतराग का भाव उनके अंदर आ गया था। परसाई ने अपने एक निबंध 'पहला सफेद बाल' में लिखा है: 'अपना कोई पुत्र नहीं। होता तो मुश्किल में पड़ जाते। क्या देते? तो इतना रंक नहीं हूं– विराट भविष्य तो है और उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। होने दो हमारे बाल सफेद। हम काम में तो लगे हैं– जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है।'

परसाई के व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो उन्हें एक अनोखा व्यंग्यकार बनाती है वो है, सच कह पाने का हौसला और उसके परिणामों को साहस के साथ स्वीकार कर पाने का जज्बा। वे जिनकी कलई खोलते, निर्भीकता के साथ खोलते थे। सन 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय में सत्ता पक्ष के विपरीत जाकर सच कह पाने का साहस परसाई के निबंधों में ही दिखता है।

राष्ट्र के धर्म–निरपेक्ष ताने–बाने को नष्ट करने वाले तत्वों को वो अपनी लेखनी के माध्यम से आड़े हाथों लेते थे। विश्वनाथ उपाध्याय लिखते हैं: 'मुझे हरिशंकर परसाई की लंबी पतली काया बंदूक की नली सी लगती है जिसमें से व्यंग्य भन्नाता हुआ निकलता है और जनशत्रु को छार–छार कर देता है।'

एक साहित्यकार के रूप में परसाई के रचना संसार की विविधता का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यतया एक सफल व्यंग्यकार (व्यंग्य संग्रहः तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडण्डियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसैं, हम इक उम्र से वाकिफ हैं, जाने पहचाने लोग) होने के साथ ही उन्होंने कहानी (कहानी–संग्रहः हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे) और उपन्यास (रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज) जैसी विधाओं में भी लेखन किया।

हालांकि उनकी रचनाधर्मिता के स्वरूप के विषय में आलोचक नामवर सिंह यह मानते हैं कि परसाई ने क्रमशः कहानियों की दुनिया को छोड़ते हुए निबंधों की दुनिया में प्रवेश किया, जहां घटनाएं सिर्फ उदाहरण के लिए प्रयोग की जाती हैं।

इस सिलसिले में स्वयं परसाई कहते थे:

'कहानी लिखते हुए मुझे यह कठिनाई बराबर आती है कि जो मैं कहना चाहता हूं, वह मेरे इन पात्रों में से कोई नहीं कह सकता। तो क्या करूं? क्या कहानी के बीच में निबंध का एक टुकड़ा डाल दूं? पर इससे कथा प्रवाह रुकेगा।'

और शायद यही वजह है कि परसाई को सबसे अधिक सफलता निबंध लेखन में ही मिली, न कि कहानियों में। हालांकि भोलाराम का जीव, कहानी हिन्दी की उत्कृष्ट व्यंग्य कहानियों में गिनी जाती है, जिसमें परसाई ने सरकारी कार्यालयों और लालफीताशाही पर प्रहार किया है।

अपने प्रसिद्ध व्यंग्य निबंध संग्रह 'विकलांग श्रद्धा का दौर' के लिए सन

शेष पेज 15 पर...

आवारा भीड़ के खतरे

हरिशंकर परसाई

एक अंतरंग गोष्ठी सी हो रही थी युवा असंतोष पर। इलाहाबाद के लक्ष्मीकांत वर्मा ने बताया–पिछली दीपावली पर एक साड़ी की दुकान पर कांच के केस में सुंदर साड़ी से सजी एक सुंदर मॉडल खड़ी थी। एक युवक ने एकाएक पत्थर उठाकर उस पर दे मारा। कांच टूट गया। आसपास के लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने तमतमाए चेहरे से जवाब दिया–हरामजादी बहुत खूबसूरत है।

हम 4–5 लेखक चर्चा करते रहे कि लड़के के इस कृत्य का क्या कारण है? क्या अर्थ है? यह कैसी मानसिकता है? यह मानसिकता क्यों बनी? बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ये सवाल दुनिया भर में युवाओं के बारे में उठ रहे हैं–पश्चिम से संपन्न देशों में भी और तीसरी दुनिया के गरीब देशों में भी। अमेरिका से आवारा हिप्पी और 'हरे राम और हरे कृष्ण' गाते अपनी व्यवस्था से असंतुष्ट युवा भारत आते हैं और भारत का युवा लालायित रहता है कि चाहे चपरासी का नाम मिले, अमेरिका में रहूं। 'स्टेट्स' जाना यानी चौबीस घंटे गंगा नहाना है। ये अपवाद हैं। भीड़–की–भीड़ उन युवकों की है जो हताश, बेकार और क्रुद्ध हैं। संपन्न पश्चिम के युवकों के व्यवहार के कारण भिन्न हैं। सवाल है–उस युवक ने सुंदर मॉडल पर पत्थर क्यों फेंका? हरामजादी बहुत खूबसूरत है–यह उस गुस्से का कारण क्यों? वाह, कितनी सुंदर है–ऐसा इस तरह के युवक क्यों नहीं कहते?

युवक साधारण कुरता पाजामा पहिने था। चेहरा बुझा था जिसकी राख में चिंगारी निकली थी पत्थर फेंकते वक्त। शिक्षित था। बेकार था। नौकरी के लिए भटकता रहा था। धंधा कोई नहीं। घर की हालत खराब। घर में अपमान, बाहर अवहेलना। वह आत्म ग्लानि से क्षुब्ध। घुटन और गुस्सा एक नकारात्क भावना। सबसे शिकायत। ऐसी मानसिकता में सुंदरता देखकर चिढ़ होती है। खिले फूल बुरे लगते हैं। किसी के अच्छे घर से घृणा होती है। सुंदर कार पर थूकने का मन होता है। मीठा गाना सुनकर तकलीफ होती है। अच्छे कपड़े पहिने खुशहाल साथियों से विरक्ति होती है। जिस भी चीज से, खुशी, सुंदरता, संपन्नता, सफलता, प्रतिष्ठा का बोध होता है, उस पर गुस्सा आता है।

बूढ़े–सयाने स्कूल का लड़का अब मिडिल स्कूल में होता है तभी से शिकायत होने लगती है। वे कहते हैं–ये लड़के कैसे हो गए? हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हम पिता, गुरु, समाज के आदरणीयों की बात सिर झुकाकर मानते थे। अब ये लड़के बहस करते हैं। किसी को नहीं मानते। मैं याद करता हूं कि जब मैं छात्र था, तब मुझे पिता की बात गलत तो लगती थी, पर मैं प्रतिवाद नहीं करता था। गुरु का भी प्रतिवाद नहीं करता था। समाज के नेताओं का भी नहीं। मगर तब हम छात्रों को जो किशोरावस्था में थे, जानकारी ही क्या थी? हमारे कस्बे में कुल दस–बारह अखबार आते थे। रेडियो नहीं। स्वतंत्रता संग्राम का जमाना था। सब नेता हमारे हीरो थे–स्थानीय भी और जवाहर लाल नेहरू भी। हम पिता, गुरु, समाज के नेता आदि की कमजोरियां नहीं जानते थे। मुझे बाद में समझ में आया कि मेरे पिता कोयले के भट्ठों पर काम करने वाले गोंडों का शोषण करते थे। पर अब मेरा ग्यारह साल का नाती पांचवीं कक्षा का छात्र है। वह सवेरे अखबार पढ़ता है, टेलीवीजन देखता है, रेडियो सुनता है। वह तमाम नेताओं की पोलें जानता है। देवीलाल और ओमप्रकाश चौटाला की आलोचना करता है। घर में उससे कुछ ऐसा करने को कहो तो वह प्रतिरोध करता है। मेरी बात भी तो सुनो। दिन भर पढ़कर आया हूं। अब फिर कहते ही कि पढ़ने बैठ जाऊं।

थोड़ी देर खेलूंगा तो पढ़ाई भी नहीं होगी। हमारी पुस्तक में लिखा है। वह जानता है घर में बड़े कब–कब झूठ बोलते हैं।

ऊंची पढ़ाईवाले विश्वविद्यालय के छात्र सवेरे अखबार पढ़ते हैं, तो तमाम राजनीति और समाज के नेताओं के भ्रष्टाचार, पतनशीलता के किस्से पढ़ते हैं। अखबार देश को चलानेवालों और समाज के नियामकों के छल, कपट, प्रपंच, दुराचार की खबरों से भरे रहते हैं। धर्माचार्यों की चरित्रहीनता उजागर होती है। यही नेता अपने हर भाषण हर उपदेश में छात्रों से कहते हैं–युवकों, तुम्हें देश का निर्माण करना है (क्योंकि हमने नाश कर दिया है) तुम्हें चरित्रवान बनना है (क्योंकि हम तो चरित्रहीन हैं) शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, नैतिक चरित्र को ग्रहण करना है–(हमने शिक्षा और अशिक्षा से पैसा कमाना और अनैतिक होना सीखा) इन नेताओं पर छात्रों–युवकों की आस्था कैसे जमे? छात्र अपने प्रोफेसरों के बारे सब जानते हैं। उनका ऊंचा वेतन लेना और पढ़ाना नहीं। उनकी गुटबंदी, एक–दूसरे की टांग खींचना, नीच कृत्य, द्वेषवश छात्रों को फेल करना, पक्षपात, छात्रों का गुटबंदी में उपयोग। छात्रों से कुछ नहीं छिपा रहता अब। वे घरेलू मामले जानते हैं। ऐसे गुरुओं पर छात्र कैसे आस्था जमाएं। ये गुरु कहते हैं छात्रों को क्रांति करना है। वे क्रांति करने लगे, तो पहले अपने गुरुओं को साफ करेंगे। अधिकतर छात्र अपने गुरु से नफरत करते हैं।

बड़े लड़के अपने पिता को भी जानते हैं। वे देखते हैं कि पिता का वेतन तो सात हजार है, पर घर का ठाठ आठ हजार रुपयों का है। मेरा बाप घूस खाता है। मुझे ईमानदारी के उपदेश देता है। हमारे समय के लड़के–लड़कियों के लिए सूचना और जानकारी के इतने माध्यम खुले हैं, कि वे सब क्षेत्रों में अपने बड़ों के बारे में सबकुछ जानते हैं। इसलिए युवाओं से ही नहीं बच्चों तक से पहले की तरह की अंध भक्ति और अंध आज्ञाकारिता की आशा नहीं की जा सकती। हमारे यहां ज्ञानी ने बहुत पहले कहा था–प्राप्तेषु षोडसे वर्षे पुत्र मित्र समाचरेत। उनसे बात की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है। कल परसों मेरा बारह साल का नाती बाहर खेल रहा था। उसकी परीक्षा हो चुकी है और एक लंबी छुट्टी है। उससे घर आने के लिए उसके चाचा ने दो–तीन बार कहा। डांटा। वह आ गया और रोते हुए चिल्लाया हम क्या करें? ऐसी तैसी सरकार की जिसने छुट्टी कर दी। छुट्टी काटना उसकी समस्या है। वह

कुछ तो करेगा ही। दबाओगे तो विद्रोह कर देगा। जब बच्चे का यह हाल है तो किशोरों और तरुणों की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी।

युवक–युवतियों के सामने आस्था का संकट है। सब बड़े उनके सामने नंगे हैं। आदर्शों, सिांतद्धों, नैतिकताओं की धज्जियां उड़ते वे देखते हैं। वे धूर्तता, अनैतिकता, बेईमानी, नीचता को अपने सामने सफल एवं सार्थक होते देखते हैं। मूल्यों का संकट भी उनके सामने है। सब तरफ मूल्यहीनता उन्हें दिखती है। बाजार से लेकर धर्मस्थल तक। वे किस पर आस्था जमाएं और किस के पदचिह्नों पर चलें? किन मूल्यों को मानें?

यूरोप में दूसरे महायुद्ध के दौरान जो पीढ़ी पैदा हुई उसे 'लास्ट जनरेशन' (खोई हुई पीढ़ी) का कहा जाता है। युद्ध के दौरान अभाव, भुखमरी, शिक्षा चिकित्सा की ठीक व्यवस्था नहीं। युद्ध में सब बड़े लगे हैं, तो बच्चों की परवाह करनेवाले नहीं। बच्चों के बाप और बड़े भाई युद्ध में मारे गए। घर का, संपत्ति का, रोजगार का नाश हुआ। जीवन मूल्यों का नाश हुआ। ऐसे में बिना उचित शिक्षा, संस्कार, भोजन कपड़े के विनाश और मूल्यहीनता के बीज जो पीढ़ी बनकर जवान हुई, तो खोई हुई पीढ़ी इसके पास निराशा, अंधकार, असुरक्षा, अभाव, मूल्यहीनता के सिवाय कुछ नहीं था। विश्वास टूट गए थे। यह पीढ़ी निराश, विध्वंसवादी, अराजक, उपद्रवी, नकारवादी हुई। अंग्रेज लेखक जार्ज ओसबर्न ने इस क्रुद्ध पीढ़ी पर नाटक लिखा था जो बहुत पढ़ा गया और उस पर फिल्म भी बनी। नाटक का नाम 'लुक बैक इन एंगर'। मगर यह सिलसिला यूरोप के फिर से व्यवस्थित और संपन्न होने पर भी चलता रहा। कुछ युवक समाज के 'ड्राप आउट' हुए। 'वीट जनरेशन' हुई। औद्योगीकरण के बाद यूरोप में काफी प्रतिशत बेकारी है। ब्रिटेन में अठारह प्रतिशत बेकारी है। अमेरिका ने युद्ध नहीं भोगा। मगर व्यवस्था से असंतोष वहां पैदा हो हुआ। अमेरिका में भी लगभग बीस प्रतिशत बेकारी है। वहां एक ओर बेकारी से पीड़ित युवक है, तो दूसरी ओर अतिशय संपन्नता से पीड़ित युवक भी। जैसे यूरोप में वैसे ही अमेरिकी युवकों, युवतियों का असंतोष, विद्रोह, नशेबाजी, यौन स्वच्छंदता और विध्वंसवादिता में प्रगट हुआ। जहां तक नशीली वस्तुओं के सेवन के सवाल है, यह पश्चिम में तो है ही, भारत में भी खूब है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण के अनुसार दो साल पहले सत्तावन फीसदी छात्र नशे के आदी बन गए थे। दिल्ली तो महानगर है। छोटे शहरों में, कस्बों में नशे आ गए हैं। किसी–किसी पान की दुकान में नशा हर जगह मिल जाता है। 'स्मैक' और 'पॉट' टॉफी की तरह उपलब्ध हैं।

छात्रों–युवकों को क्रांति की, सामाजिक परिवर्तन की शक्ति मानते हैं। सही मानते हैं। अगर छात्रों युवकों में विचार हो, दिशा हो संगठन हो और सकारात्मक उत्साह हो। वे अपने से ऊपर की पीढ़ी की बुराइयों को समझें तो उन्हीं बुराइयों के उत्तराधिकारी न बने, उनमें अपनी ओर से दूसरी बुराइयां मिलाकर पतन की परंपरा को आगे न बढ़ाएं। सिर्फ आक्रोश तो आत्मक्षय करता है। एक हर्बर्ट मार्क्यूस चिंतक हो गए हैं, जो सदी के छठवें दशक में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। वे 'स्टूडेंट पावर' में विश्वास करते थे। मानते हैं कि छात्र क्रांति कर सकते हैं। वैसे सही बात यह है कि अकेले छात्र क्रांति नहीं कर सकते। उन्हें समाज के दूसरे वर्गों को शिक्षित करके चेतनाशील बनाकर संघर्ष में साथ लाना होगा। लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आखिर क्या बदलना है यह तो तय हो। अमेरिका में हर्बर्ट मार्क्यूस से प्रेरणा पाकर छात्रों ने नाटक ही किए। हो ची मिन्ह और चे गुएवारा के बड़े–बड़े चित्र लेकर जुलूस निकालना और भद्दी,भौंड़ी, अश्लील हरकतें करना। अमेरिकी विश्विद्यालय की पत्रिकाओं में बेहद फूहड़ अश्लील चित्र और लेख कहानी। फ्रांस के छात्र अधिक गंभीर शिक्षित थे। राष्ट्रपति द गाल के समय छात्रों ने सोरोबोन विश्वविद्यायल में आंदोलन किया। लेखक ज्यां पाल सार्त्र ने उनका समर्थन किया। उनका नेता कोहने बेंडी प्रबुद्ध और गंभीर युवक था। उनके लिए राजनैतिक क्रांति करना संभव नहीं था। फ्रांस के श्रमिक संगठनों ने उनका साथ नहीं दिया। पर उनकी मांगें ठोस थी जैसे शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन। अपने यहां जैसी नकल करने की छूट की क्रांतिकारी मांग उनकी नहीं थी। पाकिस्तान में भी एक छात्र नेता तारिक अली ने क्रांति की धूम मचाई। फिर वह लंदन चला गया।

युवकों का यह तर्क सही नहीं है कि जब सभी पतित हैं, तो हम क्यों नहीं हों। सब दलदल में फंसे हैं, तो जो नए लोग हैं, उन्हें उन लोगों को वहां से निकालना चाहिए। यह नहीं कि वे भी उसी दलदल में फंस जाएं। दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उनमें युवकों की बड़ी भूमिका रही है। मगर जो पीढ़ी ऊपर की पीढ़ी की पतनशीलता अपना ले क्योंकि वह सुविधा की है और उसमें सुख है तो वह पीढ़ी कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसे युवक हैं, जो क्रांतिकारिता का नाटक बहुत करते हैं, पर दहेज भरपूर ले लेते हैं। कारण बताते हैं–मैं तो दहेज को ठोकर मारता हूं। पर पिताजी के सामने झुकना पड़ा। यदि युवकों के पास दिशा हो, संकल्पशीलता हो, संगठित संघर्ष हो तो वह परिवर्तन ला सकते हैं। पर मैं देख रहा हूं एक नई पीढ़ी अपने से ऊपर की पीढ़ी से अधिक जड़ और दकियानूसी हो गई है। यह शायद हताशा से उत्पन्न भाग्यवाद के कारण हुआ है। अपने पिता से तत्ववादी, बुनियादपरस्त (फंडामेंटलिस्ट) लड़का है।

दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारावाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती हैं। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। यह भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में यह भीड़ बढ़ रही है। इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है।

फिल्म निर्देशक चेतन आनंद और उनकी फिल्में

उठो कि डुबो दे न कहीं वक्त की धारा

जाहिद खान

दुनिया के अजीम तरीन अदीब मेक्सिम गोर्की की कहानी 'द लोअर डेफ्थ्स' पर आधारित थी। हयातुउल्लाह अंसारी और ख्वाजा अहमद अब्बास दोनों ने मिलकर, इस कहानी पर एक शानदार पटकथा लिखी। जिसमें अमीर वर्ग और गरीब तबके की जिंदगी और उनके बीच के फासले को बड़े ही खूबसूरती से दर्शाया गया था। सामंत वर्ग किस तरह से गरीबों का शोषण और उनके ऊपर अत्याचार करता है, फिल्म का केन्द्रीय विषय है। अमीर वर्ग की नजर में गरीबों की जिदगी का कोई मोल नहीं। वे उनको बड़ी हिकारत से देखते हैं। यहां तक कि उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतों से भी कोई सरोकार नहीं। अपने सुख–सुविधाओं और फायदे के लिए वे किसी भी स्तर पर उतर आते हैं। सरमायेदार अपने मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। उनकी नजर में 'विकास' की अवधारणा सिर्फ अपना ही विकास है। सत्ता से गठजोड़ कर, वह आम अवाम को ठगने में आगे आगे रहता है। आज भी यह प्रवृति खत्म नहीं हुई है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। इन जनविरोधी प्रवृतियों से तभी निपटा जा सकता है, जब जनता एकजुट हो। एकजुट होकर, उनसे संघर्ष करे। 'नीचा नगर' में यह संघर्ष भी है। यही फिल्म का मूल संदेश है कि एकता और संघर्ष से ही इस तरह की लड़ाइयों को जीता जा सकता है। निर्देशक चेतन आनंद ने इस गंभीर विषय को बड़े ही संवेदनशीलता से पिक्चराइज किया है। इस ब्लैक एंड व्हाईट फिल्म के कई सीन बेहतरीन बन पड़े हैं। खास तौर पर आंदोलित आम जन का मशाल जुलूस और यह इंकलाबी जनगीत का फिल्मांकन

उठो कि हमें वक्त की गर्दिश ने पुकारा
इंसान के एलान से दुनिया को जगा दे
सूखे हुए होंठो को नए राग सिखा दे
तहजीब की लाशों में नयी जिंदगी भर दे
कुचले हुए इंसान को इंसान बना दे
उठो कि डुबो दे न कहीं वक्त की धारा।

जाहिर है कि इस गीत में जबर्दस्त तरीके से सरमायाराना निजाम और उसके शोषण के खिलाफ संघर्ष का आह्वान है।

बहरहाल, 'धरती के लाल' की तरह 'नीचा नगर' ने भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन देश–विदेश के तमाम फिल्म समारोह में इसको खूब तारीफ मिली। फ्रांस के कांस फिल्म महोत्सव में इसे ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन ने निर्देशक चेतन आनंद के इस फिल्मी शाहकार की जमकर तारीफ की। फिल्म व्यावसायिक तौर पर भले ही कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसने भारतीय सिनेमा में एक नई धारा को जन्म दिया। आज समान्तर सिनेमा या कला सिनेमा की खूब बात होती है, भारतीय सिनेमा में चेतन आनंद ने अपनी पहली ही फिल्म 'नीचा नगर' के जरिए, इस तरह की फिल्मों की शुरुआत कर दी थी। आगे चलकर इस राह पर सत्यजित रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी आदि चले। और उन्होंने फिल्म प्रेमियों को एक से बढ़कर एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण फिल्में दीं। 'नीचा नगर' के बाद चेतन आनंद ने अनेक फिल्में बनाई। जिनमें कुछ कामयाब हुई, तो कुछ बॉक्स ऑफिस पर ठीक–ठाक रहीं।

चेतन आनंद की फिल्मों के ज्यादातर गीत मशहूर तरक्कीपसंद शायर कैफी आजमी लिखते थे। उनकी एक और महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक फिल्म 'हीर रांझा' के नगमों के अलावा इसके शायराना डायलॉग भी कैफी ने ही लिखे थे। भारतीय फिल्म इतिहास की यह इकलौती फिल्म है, जिसके संवाद काव्यात्मक अंदाज में लिखे गए हैं। अपने मधुर गीत–संगीत की वजह से 'हीर रांझा' को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। भारत–चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म 'हकीकत' (साल–1964) भी चेतन आनंद की एक लाजवाब फिल्म है। भारतीय सिनेमा में 'हकीकत' को पहली युद्ध फिल्म होने का तमगा हासिल है। चेतन आनंद ने इस फिल्म को प्रमाणिक रंग देने के लिए काफी मेहनत की थी। न सिर्फ फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशन पर की, बल्कि भारतीय सेना से भी इसमें जरूरत के मुताबिक मदद ली गई। महीनों तक फिल्म की शूटिंग जम्मू–कश्मीर के लद्दाख में हुई। जहां माइनस जीरो डिग्री टेंपरेचर में चेतन आनंद अपने कलाकारों और टेक्नीशियनों को लेकर शूटिंग के लिए डटे रहे। 'हकीकत' जब रिलीज हुई, तो इसे खूब पसंद किया गया। खास तौर से इसके युद्ध सीन और देशभक्ति जगाने वाला गीत 'कर चले हम फिदा जां...' ने दर्शकों को थिएटर हॉल के अंदर रुला दिया। इस देशभक्ति भरे गीत के अलावा फिल्म के बाकी गीत भी सुपर हिट रहे। फिल्म को प्रमाणिक रंग देने के लिए, चेतन आनंद ने इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई के दिल्ली आगमन पर हुए उनके स्वागत के फुटेज सीन भी जोड़ दिए थे। जो फिल्म में अच्छे नजर आए। साल 1965 में भारत सरकार ने 'हकीकत' को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा। भारतीय फिल्म इतिहास में आज भी 'हकीकत' एक मील का पत्थर फिल्म मानी जाती है। जब भी हमारे यहां कोई वार फिल्म बनती है, तो उसकी तुलना 'हकीकत' से होती है।

दूरदर्शन का जमाना आया, तो चेतन आनंद मनोरंजन के इस लोकप्रिय माध्यम से जुड़ गए। दूरदर्शन पर हफ्तावार प्रसारित होने वाले सीरियल के लिए उन्होंने जो सब्जेक्ट चुना, वह युद्ध और सैनिकों पर था। चेतन आनंद ने भारतीय सेना के जांबाज फौजियों के वीरता, साहस और पराक्रम को दिखाने वाले सीरियल 'परमवीर चक्र' (साल–1988) का निर्देशन किया। जिसमें परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन और युद्ध में उनकी कुर्बानियों का चित्रण था। फिल्म 'हकीकत' की तरह चेतन आनंद ने इस फिल्म की शूटिंग भी रियल लोकेशन पर की। जिसमें भारतीय सेना ने उनकी काफी मदद की। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों पर लगातार शूटिंग से उनकी सेहत बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। 'परमवीर चक्र' ही चेतन आनंद का आखिरी अहम काम था। जिसमें उन्होंने अपने निर्देशन और ख्यालात की गहरी छाप छोड़ी। चेतन आनंद एक विचारवान निर्देशक थे। उन्होंने गुलामी, और आजादी के बाद देश का नवनिर्माण देखा था, तो भारत–पाक और भारत–चीन जंग के भी गवाह रहे। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने जिन विषयों को छुआ, उनके साथ इंसाफ करने की पूरी कोशिश की। दर्शकों को स्वस्थ्य मनोरंजन दिया। साल 2013 में भारतीय सिनेमा के सौ साल मुकम्मल होने पर, भारत सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट जारी कर, इस महान फिल्म निर्देशक के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया।

सिनेमा की देशवासियों के दिलों में हमेशा एक पैठ रही है। अपने आगाज से ही इस माध्यम ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया है। मनोरंजन के साथ साथ यह माध्यम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आमजन को शिक्षित भी करता रहा है। यही वजह है कि इस माध्यम का इस्तेमाल अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से किया। ज्यादातर लोग मनोरंजन, आलमी शोहरत और मुनाफा कमाने के मकसद से फिल्मी दुनिया में पहुंचे, तो कुछ ऐसे भी दीवाने लोग थे, जिनका मकसद और इरादा फिल्मों से एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति करने का था। (हालांकि, इस पूंजीवादी संचार माध्यम से यह अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही थीं।) ख्वाजा अहमद अब्बास, बिमल राय, कृश्न चंदर, राजिंदर सिंह बेदी, शैलेन्द्र, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, सत्यजित रे, मृणाल सेन, एमएस सथ्यू और चेतन आनंद आदि उन शख्सियात में शामिल हैं। चेतन आनंद वह फिल्मकार हैं, जिन्होंने देश की पहली सामाजिक यथार्थवादी फिल्म 'नीचा नगर' निर्देशित की। और उनकी इस पहली ही फिल्म को दुनिया भर में प्रसिद्ध फिल्म फेस्टिवल, कांस में पुरस्कार से नवाजा गया। 'नीचा नगर' इस मामले में भी पहली भारतीय फिल्म बनी, जिसे किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। उस जमाने में जब भारतीय सिनेमा अपनी अलग पहचान बनाने में लगा हुआ था, यह सचमुच एक बड़ा कारनामा था। काबिल ए गौर है कि फ्रांस का यह फिल्म फेस्टिवल उस साल ही शुरू हुआ था।

चेतन आनंद, निर्माता–निर्देशक और पटकथा लेखक थे। उन्होंने आगे चलकर कई देशी–विदेशी साहित्यिक कृतियों 'अफसर' (निकोलाई गोगोल),'आखिरी खत' (ख्वाजा अहमद अब्बास) और 'हीर–रांझा' ('पंजाबी लोककथा'–वारिस शाह) को सेल्युलाइड के पर्दे पर उतारा। बीती सदी के चालीस के दशक में मायानगरी मुंबई में हीरो बनने के इरादे से पहुंचे, चेतन आनंद और देव आनंद दोनों भाई, इप्टा की स्थापना से ही इससे जुड़ गए थे। जिसमें उस वक्त चेतन आनंद बेहद सक्रिय थे। मुंबई में होने वाली इप्टा की बैठकों में वह नियमित शिरकत करते थे। संगठन ने जब रंगमंच के अलावा फिल्मों के जरिए भी हस्तक्षेप करने का इरादा किया, तो इस काम के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास के अलावा चेतन आनंद आगे आए। अब्बास ने बंगाल के अकाल पर केन्द्रित फिल्म 'धरती के लाल' के निर्देशन का जिम्मा संभाला, तो चेतन आनंद ने 'नीचा नगर' की बागडोर अपने कंधों पर ली।

'धरती के लाल' का निर्माण जहां इप्टा ने किया, तो 'नीचा नगर' इंडिया पिक्चर्स के बैनर तले बनी। जिसमें ज्यादातर कलाकार इप्टा से ही थे। यहां तक कि दोनों फिल्मों का संगीत निर्देशन पंडित रविशंकर ने दिया। मूल रूप से बंगाली नाटक 'नबान्न' और 'जबानबंदी' पर आधारित फिल्म 'धरती के लाल' जहां अली सरदार जाफरी, प्रेम धवन, वामिक जौनपुरी और नेमिचंद जैन जैसे तरकढ़कढीपसंद शायर नगमा निगारों के नगमों से सजी थी, तो 'नीचा नगर' के गीत विश्वामित्र आदिल ने लिखे। जो खुद प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे। इप्टा से सक्रिय तौर पर जुड़ी रहीं, जोहरा सहगल ने इन दोनों ही फिल्मों में न सिर्फ अदाकारी की, बल्कि 'नीचा नगर' का डांस डायरेक्शन भी संभाला। संगीतकार रविशंकर ने इन फिल्मों के गीतों में जिस तरह से कोरस का इस्तेमाल किया है, वह भी इप्टा का असर है। क्योंकि इप्टा ने ही सामूहिक गान को मुख्य धारा के संगीत का अहम हिस्सा बनाया था।

अलग–अलग समय में शुरू हुई, ये दोनों ही फिल्में 'धरती के लाल' और 'नीचा नगर' एक साथ रिलीज हुई। और वह साल था, 1946। यानी आजादी से ठीक एक साल पहले। 'नीचा नगर' को पर्दे तक पहुंचाना, चेतन आनंद के लिए आसान नहीं रहा, इसके लिए उनको काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। 'नीचा नगर' की यथार्थवादी कहानी और उसका क्लाइमेक्स देखकर, फिल्म के निवेशक ने इसके प्रदर्शन से इंकार कर दिया था। चेतन आनंद ने अपने दोस्त अफसाना निगार हयातुउल्लाह अंसारी के मार्फत इसकी खबर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचाई। नेहरू के हस्तक्षेप के बाद, फिल्म आखिरकार रिलीज हुई।

'नीचा नगर', हयातुउल्लाह अंसारी की कहानी पर बनी थी, जो रूस और

मणिपुर जल रहा है और सरकार...

पेज 16 से जारी...

" बच्चे और युवा लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं क्योंकि न तो वे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं और न ही कुछ रोजगार पाने की तलाश कर पा रहे हैं।

" राहत शिविर में रहने वाले लोगों को नहीं पता कि उनके साथ हुई हिंसा के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं और राज्य सरकार कोई मुआवजा दे रही है या नहीं। यह भी पता चला कि सरकार ने कोई कम्पेन्सेशन क्लेम कमीशन गठित नहीं किया है।

" राहत शिविरों में एक महीने के बच्चों से लेकर 80 वर्ष से अधिक के वयोवृद्ध हैं; गर्भवती महिलाएं हैं; विभिन्न बीमारियों एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के शिकार लोग वहां बिना उचित इलाज रह रहे हैं।

" सरकार द्वारा दिया जाने वाला भोजन अपर्याप्त है, विशेष तौर पर छोटे बच्चों, उम्रदराज लोगों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भोजन पर्याप्त नहीं है। स्वच्छ पेयजल, सफाई व्यवस्था और सैनिटरी पैड्स की भारी कमी है।

निष्कर्ष

राज्य में संकट जारी है और सरकार निष्क्रिय है। केंद्र सरकार की अपराधपूर्ण उदासीनता जारी संकट को और भी बढ़ा रही है। उनकी जो निष्क्रियता वहां चल रही है, उसके और पहले सरकार द्वारा कुछ चुनिंदा कार्रवाईयों के कारण हिंसा बेरोकटोक चल रही है। बच्चे और महिलाएं इसके सबसे बदतरीन शिकार हैं। मणिपुर के भयंकर हालात की स्थिति सरकार और उसके प्राइवेट एजेंडे कारण बनी है। मणिपुर के लोग चाहते हैं शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल हो। सरकार और विभिन्न सुरक्षा बलों की संदिग्ध भूमिका से वहां के लोग चिंतित हैं। सुरक्षा लोगों की अपनी स्वयं की जिम्मेदारी बन गई है। उन्हें छिटपुट हिंसक ग्रुपों के खिलाफ सतर्क रहना पड़ता है। विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर जबर्दस्त अविश्वास है, तो भी बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि जीवन और जीवन की गरिमा बहाल हो।

मांगपत्र

1. सभी ग्रुपों और व्यक्तियों को हथियारविहीन करना।

2. शांति एवं भाईचारा बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए तेजी से पहल की जाए।

3. विश्वास–निर्माण के कदमों की दिशा में पहल की जाए; जिसमें सभी पक्षों को, विशेषकर महिला संगठनों को शामिल किया जाए।

4. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का तत्काल त्यागपत्र।

5. उच्चाधिकार प्राप्त/ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और न्यायिक प्रक्रिया।

6. सभी मामलों में एफआईआर।

7. कम्पेन्सेशन क्लेम कमीशन का गठन तत्काल किया जाए और हिंसा पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए।

8. राहत शिविरों की स्थिति में तुरंत सुधार हो।

9. समयबद्ध राहत एवं रोजगार के अवसर समेत सार्थक पुनर्वासन।

10. छात्रों की शिक्षा जारी रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम।

11. दोनों तरफ उचित सुरक्षा बल के साथ बफर जोन बनाए जाए।

भाकपा का बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (पश्चिमी दिल्ली राज्य परिषद) की ओर से टाटा पावर (डीडीपीएल) कार्यालय, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र–1, दिल्ली पर बिजली की दरों में 8.7 प्रतिशत वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया गया तथा एक ज्ञापन बिजली मंत्री को भेजा गया।

प्रदर्शन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद् के सदस्य तथा एटक, दिल्ली राज्य कमेटी के उप महासचिव मुकेश कश्यप, राज्य परिषद् सदस्य तथा एटक, दिल्ली राज्य कमेटी के सचिव एस के राणा, जिला सचिव मंडल के सह सचिव राजेश कश्यप, बृजभूषण तिवारी, सुरजीत गांधी, राममूर्ति तथा अन्य विदेशी राम, बरसाती, चाँदनी आदि ने संबोधित किया और संचालन शंकर लाल जिला सचिव, राज्य सचिव मंडल व राष्ट्रीय परिषद सदस्य ने किया।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिका: भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़: प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाष: 011–23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोट: आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

'भारत जोड़ो' का साहित्यिक समारोह

पेज 8 से जारी...

विशिष्टता की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने बताया कि 'करितल' काली मिट्टी वाला सूखा, बारिश पर निर्भर क्षेत्र है। उस सूखी जगह पर, मिट्टी और मौसम के सूखेपन का प्रभाव वहाँ के लोगों के व्यवहार के रूखेपन में है। इस इलाके के लोगों को चोरों को रूप में देखने से संबंधित किवदंती का हवाला दिया जिसमें कहा जाता है कि "वहाँ के लोग पेट के बच्चे की भी चुरा लेते हैं"।

उमा देवी ने तमिल के कुछ आलोचकों द्वारा पोन्नीलन पर लगाए गए आरोप, कि यह उपन्यास 'लाल चश्मे' से लिखा गया है, का खंडन करते हुए कहा कि 'करिसल' उपन्यास में पोन्नीलन ने उस क्षेत्र में घट रही घटनाओं का यथार्थ चित्रण किया है। यह भूख के खिलाफ लड़ाई का चित्रण है। उपन्यास में वर्णित संघर्ष की घटनाओं के अनुसार गुलामी की एक–एक कतार गिर रही है। उपन्यास में महिला किरदार नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद मजबूत सकारात्मक किरदार के रूप में चित्रित हैं। उपन्यास में मौजूद वर्ग और जाति संघर्ष के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उपन्यास वर्ग और जाति में बंटे लोगों में से कुछ की आर्थिक स्थिति के नीचे गिरते और किसी अन्य की आर्थिक स्थिति के ऊपर उठने का वर्णन है। उपन्यास में वर्ग और जाति द्वन्द्व साथ–साथ चलता है, पोन्नीलन ने उन द्वंद्वों का वर्णन किया है उन पर अपना विचार व्यक्त नहीं किया है। उन्होंने साहित्यिक जगत में वर्ग और जाति दोनों को अलग–अलग देखने की कवायद के स्थान पर उनके अंतरसंबंधों के सवालों के साथ इस उपन्यास को पढ़ने और इस पर चिंतन और बहस करने का आग्रह किया।

अनुवादक प्रियदर्शिनी ने किताब पर चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने यह उपन्यास पहली बार जब पढ़ा था तब वे सातवीं कक्षा में थी। तब से उनके मन में इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद कर तमिल भाषा से इतर व्यापक पाठकों के बीच ले जाने की थी। उन्होंने अपने नाना से अपनी पढ़ाई के दौरान इस उपन्यास का अनुवाद करने की पेशकश की लेकिन वे हर बार यह कह कर मना कर देते थे कि पहले अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरा कर लो फिर करना, आखिरकार यह काम त्रिवेंद्रम स्थित अस्पताल के लिए कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम आते–जाते हुए ट्रेन यात्रा के दौरान अपने एंड्रॉयड फोन पर किया। वे हमेशा उपन्यास को अपने ऐप्रन की जेब में रखती थी, जब भी थोड़ा वक्त मिलता वो अनुवाद के काम में लग जाती थी। इस काम में इनकी कई साथियों ने अनुवाद को पढ़ कर अपने सुझाव देते हुए और इस काम में उनका हौंसला बड़ाकर मदद की। प्रियदर्शनी ने उपन्यास में वर्णित एक वेश्या किरदार के बारे में बताया कि वह साइकिल पर आती थी और उस पर बैठाकर अपने गाहकों को अपने साथ ले जाती थी। किसी ने उस महिला को बताया कि इस करिसल उपन्यास में उसका जिक्र है। उसने उपन्यास खरीदा और चूंकि वह अनपढ़ थी तो उसने किसी ओर से पढ़वाया, उस वर्णन को सुनने के बाद वह पोन्नीलन से मिलने गई और उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रियदर्शिनी ने बताया कि इसके अलावा उपन्यास की अन्य शक्तिशाली महिला पात्रों ने उन्हें काफी प्रभावित किया।

विभूति नारायण राय ने कहा की चूंकि उन्होंने उपन्यास नहीं पढ़ा है इसलिए वे अब तो जो बातचीत हुई उसके आधार पर कह सकते हैं कि 60–70 का दशक भूमि राजनीति का संघर्ष, जमीन के संघर्ष के साथ आम जनता का संघर्ष है। उन्होंने इस उपन्यास के हिन्दी में अनुवाद की जरूरत बताई।

पोन्नीलन ने अपनी लेखन प्रक्रिया के बारे में बताया कि जब वह शिक्षा अधिकारी के रूप में नगलपुरम में कार्यरत थे उस दौरान कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर घर पर उनसे मिलने आते थे और देर रात तक उनसे बातचीत होती थी, आधीरात में उनके जाने के बाद वे उनके साथ हुई बातों को डायरी में लिख लिया करते थे, यही नोट बाद में उपन्यास का स्त्रोत बने। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पहला उपन्यास 26 साल की उम्र में जब लिखा तो उस समय भारत आजाद हुआ था उसके बाद तमिलनाडु में और देश में जमींदारों और सामंतों के खिलाफ संघर्ष शुरू हुए उन संघर्षों ने उन्हें उद्वेलित किया और इस तरह समाज में चलती उथल पुथल पर उनकी लेखन प्रक्रिया चलती रही। मुझे मेरी इस किताब पर चर्चा में शामिल होते हुए, किताब के अंग्रेजी में अनुवाद किए जाने से काफी गर्व महसूस हो रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि मेरे परिवार में मेरी माँ जो कि खुद एक लेखिका थी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरे लेखन पर अपनी प्रतिक्रिया देते थे, उसमें सुधार करते थे और अब अगली पीढ़ी में भी अनुवाद के रूप में यह साहित्यिक यात्रा जारी है।

उपन्यास चर्चा कार्यक्रम के अध्यक्ष रामशरण जोशी ने सभा के समापन पर किताब पर अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत में 60– 70 के दशक में जब जमीन को लेकर किसानों, खेत–मजदूरों और जमींदारों के बीच संघर्ष चल रहे थे वह समय भारत के समाज का संक्रांति का समय था, भारत आजाद तो हो गया था लेकिन सामंती संबंधों से मुक्त नहीं हुआ था, यह वह समय था जब भारत के किसान जमींदारों से, जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे थे। उस समय के समाज में आदमी और औरत के रिश्तों में, समाज के जातिगत संबंधों और व्यवहारों में सामंती संबंधों की जकड़न से मुक्त होने की लड़ाई चल रही थी। हालांकि जाति आधारित गैर–बराबरी के संबंध अभी खत्म नहीं हुए हैं ये हमारे सामाजिक और निजी परिवेश में रोजमर्रा के व्यवहारों में प्रकट होते हैं। हमें उपन्यास की कथा पर चिंतन के साथ–साथ अपने इन गैर–बराबरी वाले व्यवहारों से भी संघर्ष करना होगा। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए अन्यत्र संदर्भ से तीन भाषा – मातृ भाषा, प्रांतीय भाषा, अंग्रेजी भाषा – सूत्र पर फिर से काम करने की याद दिलाते हुए अपनी बात समाप्त की।

कार्यक्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, हिन्दी के मशहूर लेखक असगर वजाहत, चित्रकार सवि सावरकर, प्रलेस और इप्टा से जुड़े साथी, तमिल भाषा और साहित्य अध्ययन से जुड़े कुछ छात्र, एवं कई अन्य हिन्दी, अंग्रेजी के लेखक और रंगकर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम की समाप्ति पर दिल्ली प्रलेस अध्यक्ष शंकर ने किताब चर्चा में शामिल सभी व्यक्तियों का धन्यवाद किया।

हरिशंकर परसाई: समाज की रग–रग से वाकिफ व्यंग्यकार

पेज 11 से जारी...

1982 में साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त करने वाले परसाई हिन्दी के एकमात्र व्यंग्यकार हैं। परसाई की रचनाओं के अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में हो चुके हैं।

एक व्यंग्यकार की सफलता का आकलन इसी तथ्य से किया जा सकता है कि उसके व्यंग्यों की सामाजिक सोद्देश्यता क्या है? और उसके सरोकार क्या हैं? लेखक की सामाजिक प्रतिबद्धता के विषय में परसाई के विचार थे:

'लेखक समाज का एक अंग है और उस समाज पर जो गुजरती है, उसमें सहभागी है। समाज के उत्थान और पतन, संघर्ष, सुख–दुख, आशा–निराशा, अन्याय–उत्पीड़न आदि में वह दूसरों का सहभोक्ता है।'

लेखक की समाज में फैली विसंगतियों को पहचानने की पीड़ा, उसकी व्यक्तिगत पीड़ा है जिसका समाधान वह समूह में और समूह के लिए ढूंढना चाहता है। इसीलिए अज्ञेय जिस व्यक्ति–स्वातंत्र्य की बात अपने विचारों में करते हैं, परसाई उसका सम्मान करते हुए भी व्यक्ति और व्यक्ति–निर्मित कला की एक सामाजिक सोद्देश्यता के पक्षधर हैं। परसाई कहते हैं: 'मनुष्य की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए. पर यह बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। अकेले वही सुखी है, जिन्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी। उनकी बात अलग है। अनेक लोगों को सुखी देखता हूं और अचरज करता हूं कि ये सुखी कैसे हैं। न उनके मन में सवाल उठते हैं न शंका उठती है।'

समाज के शोषितों और गरीबों के प्रति परसाई की सहानुभूति और संवेदना सिर्फ बौद्धिक ही नहीं, बल्कि क्रियात्मक भी थीं परसाई को याद करते हुए, मायाराम सुरजन ने लिखा है: परसाई के व्यंग्यों में समय और समाज की विसंगतियों और विरोधाभासों को मौके–बेमौके परास्त होते देखा जा सकता है: प्रेम विवाहों और अन्तर्जातीय विवाहों के संदर्भ में परसाई अपने एक परिचित की मान्यताओं के उत्तर में लिखते हैं: 'भगवान अगर औरत भगाये तो वह बात भजन में आ जाती है। साधारण आदमी ऐसा करे तो यह काम अनैतिक हो जाता है। जिस लड़की की आप चर्चा कर रहे हैं, वह अपनी मर्जी से घर से निकल गई और मर्जी से शादी कर ली, इसमें क्या हो गया?'

आगे, परिचित महोदय कहते हैं: आप जानते हैं, लड़का–लड़की अलग जाति के हैं?

मैंने पूछा– मनुष्य जाति के तो हैं न? कम से कम मनुष्य जाति में तो शादी हुई. अपने यहां तो मनुष्य जाति के बाहर भी महान पुरुषों ने शादी की है– जैसे भीम ने हिडिंबा से। इसी निबंध में परसाई आगे कहते हैं:

क्या कारण है कि लड़के–लड़की को घर से भागकर शादी करनी पड़ती है? 24–25 साल के लड़के–लड़की को भारत की सरकार बनाने का अधिकार तो मिल चुका है, पर अपने जीवन–साथी बनाने का अधिकार नहीं मिला।

इसी प्रकार देश में धर्म और संप्रदाय के नाम पर जिस प्रकार कट्टर अतिवादियों द्वारा मुद्दों को उछाला और अपने हितों के लिए प्रयोग किया जाता है, परसाई अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उसे भांप लेते हैं और उसके विरोध में अपनी लेखनी चलाते हैं।

आज कल के तथाकथित लव जिहाद पर परसाई का यह विश्लेषण एकदम सटीक बैठता है: 'अपने यहां प्रेम की भी जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम। एक कोई जावेद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है, तो सारे देश में लोग हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवा सकते हैं।'

इसी प्रकार, अपने एक प्रसिद्ध निबंध 'एक गोभक्त से भेंट' में उन्होंने गाय को एक प्रतीक की तरह चुनावों में भुनाने के राजनीतिक ढर्रे की पोल खोली है। परसाई, एक गोरक्षक साधु के तर्क को इस प्रकार व्यक्त करते हैं: 'जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है, तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है।

जनता कहती है हमारी मांग है, मंहगाई बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो, तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है। बच्चा, आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूँटे से बांध देते हैं। यह आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए है।'

देखा जाये तो एक व्यंग्यकार होने की परसाई की विशेषता में ही कहीं–न–कहीं उनके सबसे पहले एक नितांत मानववादी होने की विशेषता मिली हुई है। एक व्यंग्यकार के रूप में उन्होंने इस विधा को एक साहित्यिक मान्यता दिलवाई क्योंकि बात को जिस बेबाकी और खरेपन से परसाई अपने निबंधों में रखते हैं, वह शैली न केवल हिन्दी साहित्य के लिए बल्कि हिन्दी व्यंग्य के लिए भी एक नई और अनोखी बात थी। और एक मानववादी होने के नाते उनके इस व्यंग्य के केंद्र में भी मनुष्य के हित की योजना ही शामिल थी। प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे 'व्यंग्य वह है जहां कहने वाला तो अधरोष्ठों में हंस रहा हो और पर सुनने वाला तिलमिला रहा हो।'

कुछ इसी तरह की व्यंग्य क्षमता हम मध्यकालीन भक्ति संत कबीर में पाते हैं जब वह एक सुर में सभी धर्म के कट्टर तत्वों को हांक लगाते थे। इसी नजर से देखा जाये तो आधुनिक युग में व्यंग्य में सामाजिक सोद्देश्यता का पुट मिलाकर परसाई भी कबीर के ही एक नए अवतार से कम नहीं लगते।

(द वायर से साभार)

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 9 – 15 जुलाई, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 7.7.2023

एनएफआईडब्लू की फैक्ट फाईंडिंग टीम मणिपुर में

मणिपुर जल रहा है और सरकार बेसुध

एनी राजा

भारतीय महिला फेडरेशन की एक तीन सदस्यीय तथ्य–अन्वेषी टीम ने 28 जून से 1 जुलाई 2023 तक मणिपुर का दौरा किया। टीम में फेडरेशन की महासचिव एनी राजा,राष्ट्रीय सचिव निशा सिद्धू और दिल्ली की एक स्वतंत्र वकील दीक्षा द्विवेदी शामिल थी। मणिपुर में संवैधानिक संस्थान पूरी तरह निष्क्रिय हो गए हैं, जीवन का अधिकार प्रकटत: निलम्बित है और मणिपुर सरकार इस संकट के प्रति पूरी तरह निष्क्रिय एवं उदासीन है। भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन ने आवश्यक समझा कि ऐसी स्थिति में एक लोकतांत्रिक हस्तक्षेप की पहल की जाए।

मणिपुर दौरे से पहले भारतीय महिला फेडरेशन ने दिल्ली में कुकी और मैती समुदाय की उन महिलाओं से कई बार मुलाकात की जिन्हें हिंसा के कारण मणिपुर से भागना पड़ा। अपने राज्य से उखड़ी हुई इन महिलाओं से मुलाकात के बाद फेडरेशन ने इसकी आवश्यकता को समझा कि मणिपुर की स्थिति के संबंध में लोकतांत्रिक हस्तक्षेप की पहल के अपने निश्चय को तेजी प्रदान की जाए ताकि राज्य में शांति एवं स्थिरता बहाल हो और विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा रहे। काफी विचार–विमर्श और संपर्क कायम करने के बाद ही हमारी तीन सदस्यीय टीम मणिपुर जा सकी। टीम ने विभिन्न समुदाय के लोगों से मुलाकात की।

28 जून को टीम ने इम्फाल पूर्व में तीन राहत शिविरों और एक सरकारी अस्पताल (रीजनल इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सांइसिज) का दौरा किया।

29 जून को टीम ने विष्णुपुर जिले के मोईरंग में दो राहत शिविरों का दौरा किया और जिला कलेक्टर कार्यालय गई। बाद में शाम के समय टीम ने आईएमए मार्केट का दौरा किया और मीरा पाइबिस से बातचीत की।

टीम ने चूड़ाचन्दपुर के जिला कलेक्टर और विष्णुपुर के असिस्टेंट कमिशनर से भी मुलाकात की और राहत शिविरों में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए।

दौरे के तीसरे दिन यानी 1 जुलाई को टीम ने मणिपुर बेप्टिस्ट कन्वेंशन सेंटर चर्च और इम्फाल पश्चिम जिले में कैथोलिक बिशप हाउस का दौरा किया।

जब हमने अपनी यात्रा शुरू की तो हमारे मन में जो पहली और बड़ी चिंता थी वह वहां पर शांति और जीवन पर छाए खतरे के संबंध में थी। इस समय मणिपुर के लोग सामाजिक–आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनका जीवन संकटग्रस्त है।

मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वह सांप्रदायिक हिंसा नहीं है और न ही वह दो समुदायों के बीच का झगड़ा मात्र है। इसमें जमीन के सवाल, संसाधन और उन्मादग्रस्त लोगों एवं मिलिटेंटों की मौजूदगी की बातें शामिल हैं। राज्य की फासिस्ट सरकार का अपना एक छिपा कारपोरेट एजेंडा है और वह अपने उस एजेंडे पर चालाकी के साथ अमल कर रही है जिसके कारण वर्तमान संकट पैदा हुआ हैं।

सामान्य निरूपण

" यह एक राज्य–प्रायोजित हिंसा है।

" 3 मई को जो हिंसा शुरू हुई, वह अपने आप नहीं हुई, बिना किसी तैयारी के नहीं हुई। केंद्र एवं राज्य की सरकारें विभिन्न समुदायों के बीच जो अविश्वास एवं दुश्चिंता भड़का रही थी ताकि एक पूरी तरह गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए, उसकी पृष्ठभूमि में 3 मई की हिंसा हुई। मार्च और अप्रैल 2023 के महीनों में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिनसे हिंसक टकरावों की संभावना का इशारा मिलता था। परंतु सरकार ने उसकी अनदेखी की और वहशियाना हिंसा होने की इजाजत दी।

" मणिपुर का तथाकथित सामाजिक–राजनीतिक इतिहास इस तरह का रहा है जिसमें समाज दर्जावाराना तरीके से संगठित था जिसमें मैती समुदाय हावी रहा और कुकियों को ''असभ्य'' समझा जाता रहा है। संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी नीतियों के फलस्वरूप शिक्षा और सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के लिहाज से कुकियों ने कुछ हद तक सामाजिक प्रगति की है। कुकियों की इस प्रगति से बहुसंख्यक मैती समुदाय में आम तौर पर आक्रोश एवं असंतोष पैदा हुआ है।

" मणिपुर के लोगों के जीवन एवं आजीविका को बचाने के लिए कदम उठाने के बजाय सरकार भड़काने वाली कार्रवाईयां करती रही है जिससे दोनों समुदायों के बीच मनमुटाव और आक्रोश और अधिक गहरा होता है। कुछ उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं:

" सरकार द्वारा न्यू चैकोन में तीन चर्चों का इस बहाने विध्वंस कि वह अतिक्रमित जमीन पर बनी हुई थी; 2. कांगपोकी और तेनगौपान इलाकों से कुकी ग्रामीणों का निकाला जाना और वन संरक्षण एवं वन्य जीवन सुरक्षा के नाम पर उनके मकानों का ध्वंस; 3. मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति की हैसियत के संबंध में मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला; और, 4. राज्य सरकार द्वारा सस्पेंशन ऑफ आपरेशन को खत्म करने की कोशिश।

" 3 मई को 12 बजे के करीब इन बातों के खिलाफ ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, मणिपुर ने एक शांति मार्च निकाला और 3 बजे के करीब हिंसा शुरू हो गई।

" कुकी समुदाय का आरोप है कि मैती लोग शांति मार्च से नाराज थे, अत: उन्होंने पवित्र एंग्लो–कुकी स्मारक को जलाने की कोशिश की। वे बड़ी संख्या में चूड़ाचन्दपुर पहुंचे। उन्होंने पहले ही मैती और कुकी समुदाय के मकानों पर निशान लगा दिए थे।

" दोनों समुदाय एक–दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने पवित्र एंग्लो–कुकी स्मारक को गिराने की कोशिश की।

" मिलिटेंटों, उन्मादियों और शरारती तत्वों ने अशांत स्थिति का फायदा उठाया।

" 3 और 4 मई को अधिकांश मकानों को आग लगा दी गयी। लोगों ने बताया कि राज्य पुलिस समेत सशस्त्र बल हिंसा पर नियंत्रण पाने में असफल रहे थे। जिस समय मणिपुर जल रहा था मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति की मेहमाननवाजी में व्यस्त थे और 7 बजे तक ट्विटर पर तस्वीरें अपलोड कर रहे थे।

" मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति को सही तौर पर नहीं निपटा गया, इस संबंध में दोनों समुदायों के बीच आम समझ है और इससे उनमें आक्रोश एवं अप्रसन्नता है।

राहत शिविर

" अधिकांश राहत शिविर सदाशय नागरिकों और नागरिक समाज संगठनों के प्रयासों से चल रहे हैं; उन्हें सरकार का समर्थन अत्यंत सीमित है। राहत शिविर जिस हाल में हैं उससे विस्थापित एवं पीड़ित लोगों के प्रति राज्य सरकार की कोई दिलचस्पी न होने का पता चलता है। यह हिंसा–पीड़ितों की गरिमा का स्पष्टत: असम्मान है।

" शिविरों में रहने वाले अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूर और साधारण लोग हैं।

शेष पेज 14 पर...

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.